कृषि | विश्लेषण | जल प्रबंधन

कुल पृष्ठः 40

स्वदेशी पत्रिका

मूल्य 15/–रू.

आषाढ़–श्रावण 2080, जुलाई 2023

रिश्ते बराबरी के स्तर पर

स्वावलंबी भारत अभियान - बैठक

सचित्र झलक

मुंबई

भोपाल, म.प्र.

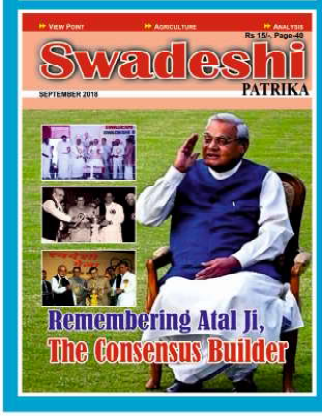

VOICE OF

SELF RELIANT INDIA

SWADESHI

Patrika

स्वदेशी

पत्रिका

पढ़ें और पढ़ायें

स्वदेशी पत्रिका

अ नु क्र म

वर्ष–31, अंक–7
आषाढ़–श्रावण 2080 जुलाई 2023

संपादक
अजेय भारती

सह–संपादक
अनिल तिवारी

पृष्ठ सज्जा एवं टंकन
सुदामा दीक्षित

कार्यालय
धर्मक्षेत्र, सेक्टर–8, बाबू गेनू मार्ग
रामकृष्णपुरम्, नयी दिल्ली–110022
से प्रकाशित

दूरभाष : 011–26184595

स्वदेशी जागरण समिति की ओर से डॉ. अश्वनी महाजन द्वारा कॉम्पीटेंट बाइन्डर्स (प्रिंटिंग यूनिट), नवीन शाहदरा, दिल्ली–32 से मुद्रित।

पाठकनामा / उन्होंने कहा **4**
समाचार परिक्रमा **36-38**

तृतीय मुख्य पृष्ठ **39**
चतुर्थ मुख्य पृष्ठ **40**

आवरण कथा – 6
रिश्ते बराबरी के स्तर पर
डॉ. अश्वनी महाजन

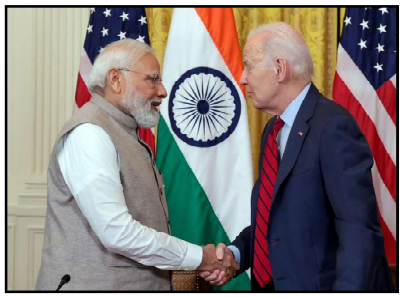

1 मुख्य पृष्ठ
2 द्वितीय मुख्य पृष्ठ

08 आवरण कथा–2
भारत–अमेरिका टैंगोः योजना के तहत रणनीतिक भागीदारी
..... के.के. श्रीवास्तव

10 आवरण कथा–3
भारत और अमेरिका की साझेदारी के मायने
..... विक्रम उपाध्याय

12 बीच–बहस
मणिपुर में हिंसाः तबाही की तह में ड्रग्स माफिया और घुसपैठिए
..... अनिल तिवारी

14 आजकल
यूसीसीः सभी के लिए नागरिक उपचार
..... डॉ. जया कक्कड़

16 जीएसटी
वस्तु एवं सेवा करः छोटे को बड़े के साथ समान अवसर प्रदान करना
..... आलोक सिंह

18 विमर्श
दुराग्रही विदेशी मीड़ियाः भारत विरोधी प्रचार में जुटी
..... डॉ. सूर्यप्रकाश अग्रवाल

20 आर्थिकी
'गिग' अर्थव्यवस्था की त्रासदी
..... स्वदेशी संवाद

22 खेती–बारी
टमाटर के बहाने बाजार का न्याय
..... देविंदर शर्मा

24 साक्षात्कार
भारत की आत्मनिर्भरता और विकास का लक्ष्य, घरेलू उद्योगों की मजबूती से दूर होगी बेरोजगारीः डॉ. अश्वनी महाजन

28 आर्थिकी
अंतरराष्ट्रीय मुद्रा के रूप में भारतीय रुपया
..... विनोद जौहरी

31 विश्लेषण
सा विद्या या विमुक्तये
..... वैदेही

34 विचार–विमर्श
भारत में किसानों की आय हो रही है दोगुनी
..... प्रहलाद सबनानी

पाठकनामा

यूसीसी का भूत

27 जून 2023 से पहले सब ठीक–ठाक चल रहा था। भाजपा और मोदी जी के खिलाफ विपक्षी पार्टियों की मुहिम राजधानी ट्रेन की गति से बढ़ रही थी। लेकिन अचानक देश के प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने 27 जून को भोपाल की एक रैली में यूसीसी (यूनिवर्सल सिविल कोड), हिंदी में कहिए तो समान नागरिक संहिता को लाने का ऐलान कर दिया। इसकी उम्मीद किसी को भी नहीं थी। यहाँ तक की भाजपा के किसी कार्यकर्ता या नेता को भी नहीं। समान नागरिक संहिता की उद्घोषणा से विपक्षी पार्टियाँ तो सकते में आ गईं 'करें तो क्या करें', क्योंकि इस आफत के विषय में तो कभी किसी ने सोचा ही नहीं था। हर राजनीतिक पार्टी का केवल एक ही ध्येय है कि येन–केन किसी भी प्रकार वह सत्ता में बनी रहे। इसके उदाहरण हमारे सामने हैं– दिल्ली, पंजाब और कर्नाटक में भारतीय जनता पार्टी को असफलता हाथ लगी। कारण रहा घोषणाएँ– शिक्षा फ्री, बिजली फ्री, हर महिला को मासिक इतना, हर बेरोजगार को मासिक इतना, वगैरह–वगैरह।

देश में हर व्यक्ति के लिए एक विधान, एक निशान, एक कानून अगर बनता है तो अच्छी बात है, यह एक अच्छी पहल है और संविधान के अनुच्छेद 44 के अनुरुप है। फिर इसका विरोध क्यों? देश के मुस्लिम भाइयों के नेता, धार्मिक गुरु (मौलाना) उनमें भ्रम फैला रहे हैं कि यदि देश में सबके लिए एक ही कानून बनाया गया तो हमारा इस्लाम खतरे में पड़ जाएगा। चार–चार शादियाँ रुक जाएंगी, संपत्ति का बंटवारा बदल जाएगा, तलाक के बाद हलाला जैसी कुरीति पर रोक लग जाएगी। हालांकि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मुस्लिम बहन–बेटियों को तीन तलाक की बीमारी से मुक्ति दिलाकर एक ऐतिहासिक कानून पास करा चुके हैं, जिससे तीन तलाक की बात अब लगभग 95 प्रतिशत तक समाप्त हो चुकी है। वे विपक्षी पार्टियाँ जो मुस्लिम वोटों को बटोरकर सत्ता पाती हैं, उनकी राजनीति खतरे में पड़ गई है।

गोवा में यूसीसी 1867 पुर्तगाली शासन में लगा और फिर 1962 में आजादी के बाद कुछ संशोधनों के साथ लगा हुआ है, कभी किसी को कोई आपत्ति नहीं हुई लेकिन आज जब यह सारे देश के लिए लगाया जा रहा है तो कुछ पार्टियाँ खुलकर इसके विरोध में आ गई हैं। अभी कई राज्यों में चुनाव होने हैं और 2024 में लोक सभा चुनाव हैं। असंभव है श्री नरेन्द्र मोदी के इस ब्रह्मास्त्र को रोक पाना।

बीएल गौड़, नोएड़ा, उत्तर प्रदेश

आवश्यक नहीं कि इस अंक के भीतर प्रस्तुत लेखकों के विचार स्वदेशी पत्रिका के संपादक मंडल के विचारों से मेल खाते हों। पाठकों की जानकारी के लिए उन्हें यहां प्रस्तुत किया जा रहा है।

संपादकीय कार्यालय

''धर्मक्षेत्र'' शिव शक्ति मन्दिर, सैक्टर–8, रामकृष्णपुरम्,
नयी दिल्ली–110022

दूरभाष : 011–26184595 • ई–मेलः
swadeshipatrika@rediffmail.com

अगर आप घर बैठे स्वदेशी पत्रिका चाहते हैं तो डिमांड ड्राफ्ट, मनीऑर्डर अथवा चेक द्वारा शुल्क *'स्वदेशी पत्रिका'* दिल्ली के नाम भेजने का कष्ट करें।

वार्षिक सदस्यता शुल्क : 150 रुपए
आजीवन सदस्यता शुल्कः 15,00 रुपए

यदि शुल्क जमा करने के उपरांत भी आपको पत्रिका समय पर उपलब्ध नहीं हो पा रही है तो तुरंत पत्रिका कार्यालय को सूचित करें।

या आप सीधे बैंक ऑफ इंडिया, खाता नं. 602510110002740
IFSC : BKID 0006025 (Ramakrishnapuram)

कहा–अनकहा

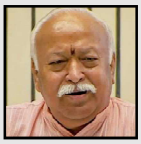

विश्व को आशा है कि सारी समस्याओं का समाधान भारत देगा।

डॉ. मोहन भागवत
सरसंघचालक, संघ

दो कानून से घर नहीं चलता तो देश कैसे चलेगा? समान नागरिक संहिता के नाम पर सिर्फ लोगों को भड़काया जा रहा है। भारत का संविधान भी नागरिकों के लिए समान अधिकारों की बात करता है।

नरेन्द्र मोदी
प्रधानमंत्री, भारत

हम नए वाहन ला रहे हैं जो पूरी तरह से इथेनॉल पर चलेंगे... स्कूटर 100 प्रतिशत इथेनॉल पर चलेंगे। मैं अगस्त में एक कार लॉन्च करूंगा, जो 100 प्रतिशत इथेनॉल पर चलेगी और यह 40 प्रतिशत बिजली भी पैदा करेगी।

नितिन गड़करी
सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री, भारत

भारत में, हम मनुष्यों सहित सभी जीवित प्राणियों को एक समान मानते हैं। यह हमारी संस्कृति रही है।

डॉ. अश्वनी महाजन
राष्ट्रीय सहसंयोजक, स्वदेशी जागरण मंच

संपादकीय

एससीओः बहुध्रुवीय विश्व व्यवस्था का अर्थशास्त्र और कूटनीति

आजकल शंघाई सहयोग संगठन (एससीओ) एक बार फिर चर्चा में है। गौरतलब है कि शंघाई सहयोग संगठन के राष्ट्राध्यक्षों का एक ऑनलाइन शिखर सम्मेलन 4 जुलाई, 2023 को आयोजित किया गया था। इस वर्ष इस संगठन की अध्यक्षता की जिम्मेदारी भारत के हाथों में है। यह पहली बार है कि संगठन के जन्म (2001) के बाद और विशेष रूप से 2016 में एससीओ में पूर्ण सदस्य के रूप में भारत के शामिल होने के बाद, भारत इसकी अध्यक्षता कर रहा है। मूल रूप से इस संगठन की स्थापना यूरोप और एशिया (जिसे यूरेशिया भी कहा जाता है) के देशों के बीच आर्थिक और रक्षा सहयोग के लिए की गई थी। एससीओ की स्थापना से पहले उज्बेकिस्तान को छोड़कर 5 देशों का एक समूह 'शंघाई फाइव ग्रुप' 1996 से काम कर रहा था। बाद में इस समूह में उज्बेकिस्तान को भी शामिल कर लिया गया और एससीओ की औपचारिक स्थापना हो गई। नई दिल्ली में प्रस्तावित इस बैठक को अचानक वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में बदल दिया गया। कुछ विशेषज्ञों का मानना है कि यह भारत के लिए अपनी स्वतंत्र विदेश नीति को प्रदर्शित करने का एक अच्छा अवसर था, और दो दिवसीय भौतिक शिखर सम्मेलन इस काम को भलीभाँति किया जा सकता था। हालाँकि इस तर्क में दम है लेकिन घटनाक्रम से पता चलता है कि इस बैठक के तरीके में बदलाव का शिखर सम्मेलन के नतीजों पर कोई खास प्रभाव नहीं पड़ा। भारतीय प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी के निमंत्रण पर, चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग, रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन, पाकिस्तान के वर्तमान प्रधानमंत्री और अन्य राज्याध्यक्षों ने बैठक में भाग लिया।

इस वर्ष ईरान को भी एससीओ की सदस्यता प्रदान की गई है। चाबहार बंदरगाह के कारण भारत की ईरान में विशेष रुचि है। 2016 से, ईरान और अफगानिस्तान के साथ एक त्रिपक्षीय समझौते के हिस्से के रूप में, भारत ने चाबहार बंदरगाह और इससे जुड़ी रेलवे लाइन के विकास के लिए एक बड़ा निवेश प्रतिबद्ध किया है। भारत ने बंदरगाह के विकास में 85 मिलियन डॉलर का निवेश किया है, और चाबहार विशेष आर्थिक क्षेत्र में 8 बिलियन डॉलर का और निवेश करने का वादा किया है। रूस की भी इस बंदरगाह और संबंधित बुनियादी ढांचे के विकास में विशेष रुचि है, क्योंकि चाबहार बंदरगाह होर्मुज जलडमरूमध्य के बाहर स्थित है, यह रूस को मध्य पूर्व से माल भेजने के लिए एक वैकल्पिक मार्ग प्रदान करेगा। एससीओ में ईरान के प्रवेश से रूस और भारत के सहयोग से इस परियोजना को आगे बढ़ाने का मार्ग प्रशस्त होगा।

शिखर सम्मेलन के अंत में, हालांकि नई दिल्ली घोषणा नामक एक घोषणा की गई थी, जो व्यापक सहमति को रेखांकित करती है, लेकिन दो प्रमुख मुद्दों, यानि 'बेल्ट रोड पहल' (बीआरआई) और 'विकास रणनीति 2030' पर मतभेदों को इंगित करते हुए इस घोषणा पत्र को सावधानीपूर्वक तैयार किया गया। नई दिल्ली घोषणा के अलावा, कुछ हस्ताक्षरित समझौतों में बेलारूस गणराज्य के दायित्वों का ज्ञापन, और कट्टरवाद और डिजिटल परिवर्तन पर दो बयान शामिल हैं। यह समझना महत्वपूर्ण है कि भारत संप्रभुता के मुद्दे पर बीआरआई का विरोध करता रहा है। गौरतलब है कि चीन, पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर (पीओके) में चीन–पाकिस्तान आर्थिक गलियारा (सीपीईसी) बना रहा है और भारत लगातार इसका विरोध करता रहा है। इसके अलावा, भारत के मुताबिक, बीआरआई कई विकासशील देशों के लिए कर्ज का जाल साबित हो रहा है और बीआरआई ने पाकिस्तान, श्रीलंका समेत कई देशों की अर्थव्यवस्थाओं को खतरे में डाल दिया है। चीन कई देशों को कर्ज के जाल में फंसाकर रणनीतिक स्थानों पर जबरन कब्जा कर रहा है और इस तरह यह वैश्विक शांति के लिए खतरा साबित हो रहा है। एक और मुद्दा, जिस पर भारत सहमत नहीं था, वह था विकास रणनीति 2030 पर दस्तावेज़। भारत ने पहले ही वैश्विक विकास पहल के समान, दस्तावेज़ पर चीनी प्रभाव के बारे में अपनी चिंताओं को चिह्नित किया था, और दस्तावेज़ की भाषा को बनाए रखने पर आपत्ति जताई थी। .

आज रूस और ईरान अमेरिका और उसके सहयोगियों द्वारा लगाए गए प्रतिबंधों के शिकार हैं। एससीओ के सदस्यों भारत और चीन ने न केवल रूस और ईरान से तेल खरीदना जारी रखा है, बल्कि इसे कई गुना बढ़ा दिया है। इससे अमेरिका और पश्चिमी देश परेशान हैं, लेकिन भारत ने अमेरिका के साथ अपने मैत्रीपूर्ण संबंध जारी रखते हुए एक संतुलित दृष्टिकोण अपनाया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की हालिया अमेरिका यात्रा भारत के स्वतंत्र दृष्टिकोण का संकेत है। हालाँकि, दूसरी ओर, रूस और चीन आर्थिक और रणनीतिक मामलों में अपने सहयोग को गहरा कर रहे हैं। लेकिन रूस के साथ भारत की सदाबहार दोस्ती भारत और रूस दोनों के लिए वरदान साबित हो रही है। भारत ने रूस–यूक्रेन संघर्ष के संबंध में भी तटस्थ रहना चुना है। हालाँकि, एससीओ के ऑनलाइन शिखर सम्मेलन में रूस और चीन का रवैया खुल कर सामने आया, जिन्होंने मुखर रूप से अमेरिकी प्रतिबंधों को अस्वीकार कर दिया। लेकिन साथ ही चीन के नेतृत्व वाले बीआरआई और चीन के प्रभुत्व वाली विकास रणनीति 2030 पर भारत की अस्वीकृति ने भारत की अडिगता प्रदर्शित की है। एससीओ का संदेश बहुत स्पष्ट है, अंतर्राष्ट्रीय कूटनीति कभी भी पूरी तरह से पारदर्शी नहीं होती है, लेकिन एससीओ बहु–ध्रुवीय दुनिया की वास्तविकता को रेखांकित करता है। आज जब विश्व स्तर पर बहुत सारे मंथन हो रहे हैं, शक्ति संतुलन बनाए रखने के लिए एससीओ जैसे समूहों का बहुत महत्व है।

रिश्ते बराबरी के स्तर पर

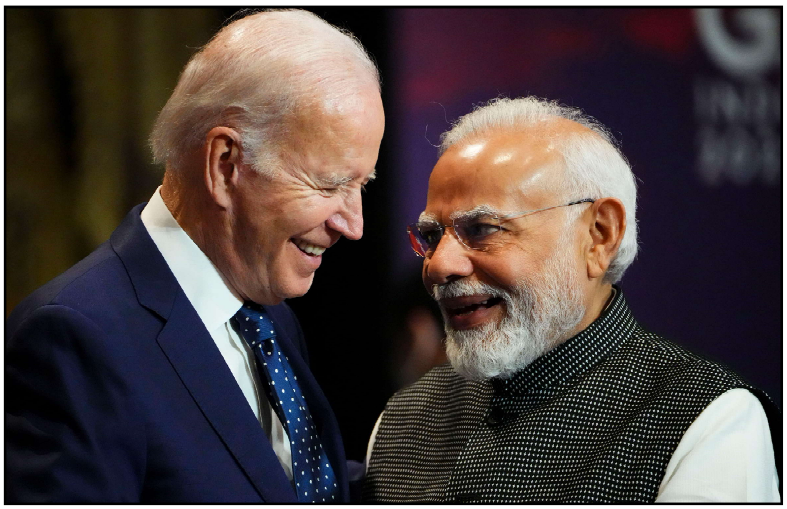

हाल ही में संपन्न प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का अमेरिका दौरा काफी सुर्खियों में रहा था। वैसे तो भारतीय प्रधानमंत्रियों की सभी यात्राएँ उस समय के समाचार मीडिया के लिए बड़ी उत्सुकता और आकर्षण का विषय रहती रही हैं, लेकिन प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी की हालिया अमेरिका यात्रा और भारत और अमेरिका के बीच आर्थिक और व्यापारिक निर्णय, रणनीतिक खरीद, प्रौद्योगिकी सहयोग और व्हाइट हाउस में प्रधानमंत्री का गर्मजोशी से स्वागत, सभी ने भारत के लोगों को एक सुखद एहसास दिया है।

इन दोनों महान लोकतंत्रों के बीच रिश्ते इतिहास में बहुत अच्छे नहीं रहे हैं। और आज भी संयुक्त राज्य अमेरिका में कुछ ऐसे तत्व हैं, जो अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, प्रेस की स्वतंत्रता, जातीय अल्पसंख्यकों की सुरक्षा, लोकतंत्र आदि के फर्जी आख्यानों के आधार पर भारत पर उंगलियां उठाते रहते हैं और अतीत में ये तत्व सफल भी रहे हैं। आधिकारिक कार्यवाही में आधिकारिक बयानों, कथनों आदि पर इसकी छाया देखने को मिलती रही है। पीएम मोदी की यात्रा की सफलता इस बात से पता चलती है कि शायद कूटनीतिक तौर पर यह पहले से तय था कि पीएम मोदी की राजकीय यात्रा के दौरान इस तरह की कोई बयानबाजी नहीं की जाएगी। यह रिश्तों में समानता की स्पष्ट अभिव्यक्ति है।

फिलहाल अगर भारत–अमेरिकी संबंधों की बात करें तो ये रिश्ते आर्थिक, रणनीतिक, तकनीकी सहयोग के साथ–साथ दोनों देशों के लोगों के बीच बढ़ते रिश्तों के भी हैं।
– डॉ. अश्वनी महाजन

राष्ट्रपति बाईडेन और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संयुक्त बयान में कहा गया है कि दोनों देश "अमेरिकी और भारतीय उद्योग, सरकार और शैक्षणिक संस्थानों के बीच अधिक प्रौद्योगिकी साझाकरण, सह–विकास और सह–उत्पादन के अवसरों की सुविधा प्रदान करेंगे।" यह उल्लेखनीय है कि भारत ने कृत्रिम बुद्धिमत्ता, क्वांटम कंप्यूटिंग, अंतरिक्ष और दूरसंचार जैसी आगामी प्रौद्योगिकियों के क्षेत्र में उल्लेखनीय प्रगति की है। भारत और अमेरिका ने इन क्षेत्रों में मिलकर काम करने का फैसला किया है। यह दो महान आर्थिक और प्रौद्योगिकी महाशक्तियों के बीच प्रगाढ़ होते संबंधों का प्रकटीकरण है।

पीएम मोदी की अमेरिका यात्रा इस वजह से भी अधिक महत्वपूर्ण है क्योंकि आज अमेरिका आर्थिक, कूटनीतिक और रणनीतिक रूप से बड़ी चुनौतियों का सामना कर रहा है। विश्व भारत को एक महत्वपूर्ण खिलाड़ी के रूप में देखता है, जिसकी वर्तमान विश्व अर्थव्यवस्था में भूमिका है। इतिहास में एक समय था जब अमेरिकी डॉलर (यूएसडी) दुनिया पर हावी था, यूएसडी का वैश्विक आरक्षित मुद्रा का 70 प्रतिशत हिस्सा था; आज यह घटकर लगभग 54 प्रतिशत रह गया है। अमेरिका इस समय सदी की सबसे ऊँची महंगाई दर के बीच है। अफगानिस्तान से अचानक सेना की वापसी और वहां कट्टरपंथी सरकार के उदय के बाद दुनिया के दादा का दर्जा काफी घट गया है। रूस–यूक्रेन संघर्ष में पूरी तरह से

विफलता, और यूक्रेन की लगातार हानि और परिणामस्वरूप ऊर्जा और सामान्य मुद्रास्फीति और दुनिया भर में उत्पादन को प्रभावित करने वाली आपूर्ति श्रृंखला में व्यवधान ने एक महाशक्ति के रूप में अमेरिकी कमज़ोरी को उजागर किया है। इन परिस्थितियों में, अमेरिका के लिए ऐसे साझेदार ढूंढना अनिवार्य है जो सक्षम भी हों और भरोसेमंद भी। लोकतंत्र हमेशा से अमेरिका का मुख्य मुद्दा रहा है और जिस देश को अमेरिका अपना मुख्य शत्रु मानता है, यानी चीन, वहां भी निरंकुश शासन है। चीन का पड़ोसी और एक सबसे बड़ा लोकतंत्र होने के नाते भारत संतुलन स्थापित करने में अमेरिका की मदद कर सकता है। क्वाड के साथ प्रौद्योगिकी सहयोग उस सोच का स्वाभाविक परिणाम है। एक अमेरिकी राजनयिक का हालिया बयान कि रूस और यूक्रेन के बीच चल रहे युद्ध में भारत मध्यस्थ की भूमिका निभा सकता है, जटिल से जटिल विवादों को भी सुलझाने में भारतीय नेतृत्व के बढ़ते दबदबे का संकेत है।

अतीत में, अमेरिका महान और शक्तिशाली राष्ट्र के खुमार में जी रहा था। इसलिए भारत–अमेरिकी रिश्ते उस खुमारी से बाहर नहीं आ सके। पूर्व में हमने अंतर्राष्ट्रीय व्यापार वार्ताओं में भारत के वाणिज्य मंत्री के समकक्ष स्थिति वाले अमेरिकी व्यापार प्रतिनिधियों (यूएसटीआर) का अहंकारपूर्ण रवैया भी देखा है। लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अमेरिका यात्रा से पहले यूएसटीआर के भारत आने–जाने पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया गया।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अमेरिका यात्रा को हमें व्हाइट हाउस में उनके स्वागत या जश्न की धूमधाम के नजरिये से नहीं देखना चाहिए। हमें इस यात्रा के अर्थ और परिणामों का विश्लेषण करना होगा, तभी हम भारत–अमेरिका संबंधों के नए अध्याय को बेहतर ढंग से समझ पाएंगे।

गौरतलब है कि अतीत में भारत और अमेरिका के रिश्ते आमतौर पर असमान रहे हैं। इतना ही नहीं, रणनीतिक तौर पर अमेरिका ज्यादातर पाकिस्तान का समर्थक रहा है। कुल मिलाकर शीत युद्ध के समय से भारत और अमेरिका के रिश्तों में अगर कोई कड़वाहट नहीं थी तो कोई अधिक सौहार्द भी नहीं था। लेकिन सोवियत रूस के पतन, चीन के आर्थिक उद्भव और भारतीय अर्थव्यवस्था में लगातार प्रगति के साथ भारत और अमेरिका के संबंधों में नए अध्याय जुड़े। वर्ष 2000 में, तत्कालीन अमेरिकी राष्ट्रपति बिल क्लिंटन ने भारत का दौरा किया और नागरिक परमाणु सहयोग पर एक ऐतिहासिक समझौते पर भी हस्ताक्षर किए, जिसने भारत और अमेरिका के बीच व्यापार और निवेश में एक नया अध्याय खोला; और दोनों देशों के बीच रणनीतिक साझेदारी शुरू हुई। इस बार मोदी की यात्रा के दौरान जीई कंपनी द्वारा फाइटर जेट के इंजन में ऐतिहासिक प्रौद्योगिकी हस्तांतरण को अमेरिका की पिछली नीति से बड़े बदलाव के रूप में देखा जा रहा है।

दूसरी ओर, चीन के बढ़ते दबदबे और एक महाशक्ति के रूप में अमेरिका को उसकी चुनौती के कारण भारत अमेरिका का स्वाभाविक रणनीतिक साझेदार बनकर उभरा। भारत, अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया का क्वाड उसका एक स्वाभाविक परिणाम था।

फिलहाल अगर भारत–अमेरिकी संबंधों की बात करें तो ये रिश्ते आर्थिक, रणनीतिक, तकनीकी सहयोग के साथ–साथ दोनों देशों के लोगों के बीच बढ़ते रिश्तों के भी हैं। माना जा रहा है कि आने वाले सालों में भारत और अमेरिका के बीच ये रिश्ते और प्रगाढ़ होंगे और वैश्विक चुनौतियों के लिहाज से भी दोनों देशों का एक साथ आगे बढ़ना जरूरी माना जा रहा है।

पिछले करीब एक दशक में भारत और अमेरिका के रिश्तों में नई गर्माहट देखने को मिल रही है। भारत एक महत्वपूर्ण भागीदार देश और पहले से अधिक शक्तिशाली बनकर उभरा है। पिछले कुछ वर्षों में, पहले मेक इन इंडिया और बाद में आत्मनिर्भर भारत योजना के तहत, भारत रणनीतिक उपकरणों में आत्मनिर्भरता की ओर बढ़ रहा है। इसके चलते न सिर्फ भारत का रूस के साथ–साथ अमेरिका समेत पश्चिम से रक्षा सामान का आयात कम हो रहा है, बल्कि भारत दुनिया के अलग–अलग हिस्सों में रक्षा सामान का निर्यात भी करने लगा है। अंतरिक्ष, सॉफ्टवेयर, कंप्यूटिंग और भुगतान समेत विभिन्न प्रकार की प्रौद्योगिकियों के क्षेत्र में भारत की उल्लेखनीय प्रगति देखी जा रही है।

अमेरिका द्वारा अपने आत्मनिर्भरता प्रयासों के जवाब में भारत से आने वाले कई उत्पादों पर टैरिफ बढ़ाने और भारत द्वारा जवाबी कार्रवाई में कई अमेरिकी उत्पादों पर आयात शुल्क बढ़ाने के कारण व्यापार के क्षेत्र में संबंध कुछ हद तक तनावपूर्ण हो गए थे । अब भारत और अमेरिका दोनों ने अपने आर्थिक हितों को देखते हुए अपने व्यापार विवादों को खत्म करने का फैसला किया है, प्रधानमंत्री की वर्तमान अमेरिकी यात्रा के दौरान यह निर्णय लिया गया है कि भारत अमेरिकी उत्पादों पर जवाबी टैरिफ वापस ले लेगा, जो उसने अमरीका द्वारा हमारे उत्पादों पर टैरिफ बढ़ाने के जवाब में लगाये थे, और दूसरी ओर, अमेरिका भी विश्व व्यापार संगठन में अपने भारत के विरुद्ध अपने विवाद वापस लेगा। इस बराबरी के समझौते को भारत और अमेरिका के रिश्तों में एक नया अध्याय माना जा रहा है, जहां कोई भी फैसला एकतरफा नहीं होता। ❑❑

भारत-अमेरिका टैंगोः
योजना के तहत रणनीतिक भागीदारी

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अमेरिका यात्रा भारत अमेरिकी संबंधों को प्रगाढ़ता प्रदान करने के मद्देनजर ऐतिहासिक करार दी जा रही है। दरअसल इस दौरान विश्व के दो सबसे बड़े लोकतांत्रिक देशों के बीच अनेक समझौतों पर हस्ताक्षर हुए हैं। इनसे यकीनन भारत को खासतौर पर रक्षा क्षेत्र में काफी मजबूती मिल सकेगी। राष्ट्रपति जो बाइडन की ओर से प्रधानमंत्री मोदी के अतिथि सत्कार की वास्तविक मंशा और इस सफल यात्रा से भारत की विकास यात्रा की गति के बारे में लंबे समय तक विश्लेषण किया जाएगा। दोनों देशों के बीच वाणिज्यक, आर्थिक, रणनीतिक तकनीकी और रक्षा हितों के मुद्दों को रेखांकित किया गया। इस यात्रा और इसके नतीजे एक बहुलवादी लोकतांत्रिक समाज के रूप में भारत की नरम शक्ति के अलावा एक उभरती हुई आर्थिक और रणनीतिक शक्ति के रूप में भारत के उत्थान की ओर स्पष्ट संकेत करता है।

अमेरिका के साथ भारत का जुड़ाव गहरा, मजबूत और अधिक व्यापक होता जा रहा है लेकिन भारत ने अपनी रणनीतिक स्वायत्तता से समझौता न करने के उद्देश्य पर अपेक्षित ध्यान नहीं दिया है। अमेरिका अभी भी एक द्विध्रुवीय दुनिया चाहता है, जिसके साथ भारत सहज नहीं है।
– के.के. श्रीवास्तव

लगभग साढे चार मिलियन भारतीयों की आबादी के साथ हमारा प्रवासी समाज अमेरिका में दूसरा सबसे बड़ा आप्रवासी समुदाय है। वैज्ञानिक संस्थानों, सुरक्षा केंद्रों, तकनीकी केंद्रों, राजनीति सरकार और अन्य व्यवसाय में भी भारतीयों ने अमेरिका में अपनी एक स्थाई जगह बना ली है। प्रधानमंत्री की यात्रा से दो बड़े लोकतांत्रिक देशों, उनके लोगों, सरकारों, व्यापार और प्रतिष्ठानों के बीच जुड़ाव के स्तर को और गहरा कर दिया है। टेस्ला, एप्पल, गूगल, माइक्रोसॉफ्ट जैसे अमेरिकी कारोबार के शीर्ष लोगों के साथ बैठक में स्वास्थ्य, रक्षा, उच्च स्तरीय विनिर्माण के साथ–साथ तकनीकी और प्रौद्योगिकी क्षेत्र के लिए सरकारी और निजी व्यवसाय को लेकर बड़े समझौते हुए। इससे दोनों देशों के बीच गहरे स्तर पर रणनीतिक संरेखण का संकेत मिलता है।

जीई, एचएएल के तेजस विमान के लिए भारत में एंगल्स का उत्पादन करेगा। यह एक प्रमुख रक्षा सौदा है जिसमें प्रौद्योगिकी हस्तांतरण भी शामिल है। माइक्रोन भारत में 2.75 बिलियन डालर की सेमीकंडक्टर असेंबली और परीक्षण सुविधा के लिए 800 मिलियन डॉलर से अधिक का निवेश भारत में करेगा। यह चीन ताइवान की जोड़ी के लिए वैकल्पिक आपूर्ति श्रृंखला विकसित करने की दिशा में प्रगति पर किया गया काम है। इसके लिए 60000 भारतीय इंजीनियरों को प्रशिक्षित किया जाएगा। इसी तरह खनिज के क्षेत्र में हुई साझेदारी काटिकल खनिज आपूर्ति श्रृंखला में विविधता लाएगी और उन्हें सुरक्षा प्रदान करेगी। इससे चीनी प्रभुत्व को कम करने में मदद मिलेगी। चीन के प्रभुत्व को आंकते हुए भारत की इंडो–पेसिफिक में एक बड़ी भूमिका है। भारत और अमेरिका दोनों इस बात को भली प्रकार समझते भी हैं। चीन को रोकने के लिए अमेरिका भारत की अनदेखी नहीं कर सकता और

लगता है कि इस लक्ष्य को हासिल करने के लिए अमेरिका ने यूक्रेन रूस संघर्ष पर भारत और अमेरिका के बीच मतभेदों को भी कम करने का फैसला किया है।

यात्रा के दौरान डब्ल्यूटीओ से संबंधित विवादों का भी समाधान किया गया इनसे भारत के इस्पात, एलमुनियम और नवीकरणीय ऊर्जा उद्योगों में मदद मिलेगी। बेंगलुरु और अहमदाबाद में नए अमेरिकी वाणिज्य दूतावास खोले जाएंगे वही एचआईवी और एल बीजा धारक अब भारत लौटे बिना अमेरिका में ही अपने वीजा का नवीकरण करा सकेंगे। इस यात्रा को लेकर कुछ प्रमुख पश्चिमी देशों ने भारत पर नए राग अलापने भी शुरू कर दिए। निश्चित रूप से भारत द्वारा किलर ड्रोन और वाणिज्यिक विमानों के लिए बड़े पैमाने पर आर्डर अमेरिकी मीडिया, व्यापार और सरकार के हृदय परिवर्तन में एक बड़ा योगदान किया है। किसी भी समझदार व्यक्ति के लिए यह तथ्य अपरिहार्य होना चाहिए कि नरम और कठोर दोनों शक्तियों ने अपनी अपनी भूमिकाएं निभाई हैं। भारत ने जहां संयम का परिचय दिया है वहीं अमेरिका ने एक तरह से भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को दुनिया का सबसे लोकप्रिय नेता घोषित कर दिया है।

इसमें कोई दो राय नहीं कि भारत की बढ़ती हुई शक्ति मुख्य रूप से द्विपक्षीय संबंधों को मजबूत करने की अहम कड़ी है। भारतीय बाजार के बढ़ते आकार को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। इस प्रकार भारत एकमात्र लोकतांत्रिक राष्ट्र है जो सभी क्षेत्रों वाणिज्य आर्थिक राजनीतिक, प्रभाव, कूटनीति आदि के मोर्चे पर चीनी विस्तारवादी नीतियों और उनके द्वारा की जा रही डिजाइनों से मिलने वाली चुनौतियों का मुकाबला कर सकता है। चीन का सर्कल घरेलू उत्पाद लगभग 30 ट्रिलियन डॉलर का है। वर्तमान अमेरिकी डालर के संदर्भ में भी चीन की अर्थव्यवस्था दुनिया में दूसरी सबसे बड़ी है। यही वह बिंदु है जहां पहुंचकर अमेरिका के लिए भारत और भारत के लिए अमेरिका का महत्व बढ़ जाता है। बोइंग के साथ इंडिगो और एयर इंडिया के बीच हस्ताक्षरित सैकड़ों वाणिज्यिक विमान सौदों को देखें तो पारस्परिक रूप से लाभप्रद रिश्ते की तस्वीर उभर कर आती है। भारत दुनिया की पांचवीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था वाला देश है जो जल्द ही तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने की ओर अग्रसर है। यहां यह उल्लेखनीय है कि भारतीय अर्थव्यवस्था अमेरिकी अर्थव्यवस्था के आकार का केवल 15 प्रतिशत है लेकिन भारत अमेरिकी योगदान का 60 प्रतिशत (विश्व विकास में) योगदान देता है, क्योंकि भारत की जीडीपी वृद्धि सालाना दर पर अमेरिका की तुलना में लगभग 4 गुना तेज है।

भारत ही एक ऐसा देश है जो हिंद महासागर में चीन के नापाक मंसूबों को नाकाम कर सकता है। भारत की सेना को अमेरिकी पोसीडॉन वायुसेना के विमानों और दलों के आदेश से मजबूत किया जा रहा है जो दुश्मन से निगरानी और हमले में शोर करने में मदद करेंगे। दरअसल अमेरिकी रक्षा उत्पाद निर्माता भारतीय बाजार को लेकर उत्साहित हैं क्योंकि भारत दुनिया का सबसे बड़ा रक्षा आयातक देश है और इसका रक्षा बजट दुनिया का चौथा सबसे बड़ा रक्षा बजट है।

दोनों देशों के बीच हुए समझौते और संबंध निहितार्थों के मोर्चे पर ऐतिहासिक हैं। शेष दुनिया इस बारे में सुराग खोज रही है कि अमेरिका भारत के बीच गहरी होती भागीदारी विश्व व्यवस्था को किस तरह से प्रभावित कर सकती है। एक ऐसी व्यवस्था, जो जल्द ही अमेरिका की तुलना में यहां एशियाई प्रभुत्व स्थापित कर सकती है जिसमें भारत और चीन दोनों शामिल है। लोकतंत्र और निरंकुशता के बीच चुनौती स्वाभाविक है, लेकिन रूस के साथ भारत के रिश्ते आडे नहीं आए। इसीलिए दौरे के दौरान फोकस रूस और चीन के बीच नोलिमिट दोस्ती पर ही रहा, जिसका मतलब है कि इंडो–पेसिफिक क्षेत्र को सुरक्षित करना होगा। अमेरिका को भारत द्वारा रूसी तेल की खरीद या मिसाइल रोधी गोलीबारी की खरीद को दरकिनार करना पड़ा। क्योंकि इंडो पेसिफिक को मजबूत करने के लिए इतिहास की झिझक को बुलाकर दोनों देशों के बीच घनिष्ठ आलिंगन के लिए व्यवहारिकता की पर्याप्त खुराक की आवश्यकता थी।

दोनों देशों द्वारा निर्धारित रणनीति के एजेंडे में निश्चित रूप से वाणिज्यिक समझौते शामिल थे। भारत के आर्थिक उत्थान से विश्व को मदद मिलेगी क्योंकि भारत एक संभावित बाजार उपलब्ध कराएगा। बदले में हमें जो प्रौद्योगिकी हस्तांतरण मिलेगा वह दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने में सहायक के रूप में कार्य करेगा। दोनों देश इस दिशा में लगातार काम कर रहे हैं। यहां दोनों देशों ने समझा है कि शून्य राशि वाला खेल संभव नहीं है, यह पूरी तरह से लेन–देन पर आधारित है।

अमेरिका के साथ भारत का जुड़ाव गहरा, मजबूत और अधिक व्यापक होता जा रहा है लेकिन भारत ने अपनी रणनीतिक स्वायत्तता से समझौता न करने के उद्देश्य पर अपेक्षित ध्यान नहीं दिया है। अमेरिका अभी भी एक द्विध्रुवीय दुनिया चाहता है, जिसके साथ भारत सहज नहीं है। फिर भी एक तरफ अपनी सीमा और संप्रभुता की रक्षा करने और दूसरी तरफ अपने आर्थिक हितों को बढ़ाने की भारत की इच्छा अमेरिकी हितों के अनुरूप है, वह यह भी जानता है। आशा की जानी चाहिए कि आपसी विश्वास और समायोजन की नई सुबह से दो बड़े लोकतंत्रों का सहजीवी विकास होगा। ❑❑

भारत और अमेरिका की साझेदारी के मायने

सोच बदलिए, परिणाम बदल जाएगा। प्रधानमंत्री मोदी के अमेरिकी दौरे की सबसे बड़ी उपलब्धि ही यही रही कि राष्ट्रपति बाइडेन ने एक बार नहीं, कई बार यह संकेत दिया कि भारत के प्रति अमेरिकी सोच में बहुत बड़ा बदलाव आया है। उनकी यह घोषणा कि 21 वीं सदी भारत और अमेरिका की होगी, इसकी पुष्टि करती है। नई दिल्ली और वाशिंगटन के बीच सुरक्षा, तकनीक, माइक्रोचिप्स और वीजा की सहूलियतें जैसे दर्जनों समझौते दोनों देशों के बीच विश्वास बहाली के परिणाम हैं।

तीन साल पहले तक अमेरिका नई दिल्ली के साथ एक संतुलन की नीति पर काम कर रहा था। पाकिस्तान उसके लिए मजबूरी था, लिहाजा इस्लामाबाद को एक दम नजरअंदाज कर भारत को एक रणनीतिक साझीदार नहीं बना सकता था। लेकिन जब अमेरिका मई 2021 में अफगानिस्तान को पूरी तरह खाली कर निकल गया तो उसके सामने भारत के साथ अपनी साझेदारी बढ़ाने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। भारत को संतुष्ट करने के लिए बाइडेन ने राष्ट्रपति बनने के बाद एक बार भी पाकिस्तान के प्रधानमंत्री से बात नहीं की। इमरान खान बाइडेन के एक फोन कॉल के लिए तरसते रह गए।

अमेरिका का निवेश एशिया में सबसे ज्यादा चीन में है। 2021 में यह 118 अरब डॉलर था, जबकि भारत में लगभग 60 अरब डॉलर। कोविड काल और उसके बाद चीन में अमेरिकी निवेश खतरे में है। व्यावसायिक कटुता इतनी बढ़ गई है कि चीन से अमेरिकी कंपनियां लगातार बाहर जा रही हैं। चीन के अलावा पूरी दुनिया में भारत ही एक ऐसा देश है, जहां सस्ते और पर्याप्त संख्या में मजदूर उपलब्ध हैं। अंग्रेजी बोलने वाले पेशेवर लोग हैं। आईटी और उससे जुड़ी सेवाओं की भरमार है और प्रधानमंत्री मोदी की सत्ता में आने के बाद से नीतियों में निरंतरता और राजनीति स्थिरता बरकरार है।

यही कारण है कि चीन से उठ कर बाहर जाने वाली हर अमेरिकी कंपनी के लिए भारत सर्वोच्च प्राथमिकता वाली डेस्टिनेशन बन गया है। अब एप्पल अकेला उदाहरण नहीं है, जो

भारत और अमेरिका के बीच संबंधों की ऊंचाई का नया पड़ाव इसी साल सितंबर में तब आएगा, जब जी–20 राष्ट्राध्यक्षों की बैठक में भाग लेने अमेरिकी राष्ट्रपति बाइडेन नई दिल्ली आएंगे।

– विक्रम उपाध्याय

अपनी उत्पादन इकाई भारत में लाकर खुश है। प्रधानमंत्री मोदी की इस अमेरिकी यात्रा के बाद भारत में टेस्ला, माइक्रोन टेक्नोलॉजी, बोइंग, एमैजन, फॉक्सकॉन, सिस्को, वालमार्ट, जनरल इलेक्ट्रिक जैसी कंपनियां भारत में अपना कारोबार बढ़ाने के लिए तत्पर हो गई हैं।

भारत के साथ फाइटर जेट के इंजन और ड्रोन की आपूर्ति और निर्माण के लिए अमेरिकी कंपनियों की प्रधानमंत्री मोदी के सामने जताई गई सहमति केवल व्यापारिक हितों के लिए नहीं है। इसके पीछे अमेरिका की अपनी सुरक्षा नीति है। चीन की आक्रामता रोकने के लिए यूएस प्रशासन ने जो रणनीति बनाई है, वह कुछ हद तक नाटो की रणनीति से मिलती जुलती है। क्वाड एशिया में वही काम करेगा जो यूरोप और अमेरिका में नाटो कर रहा है। जापान और ऑस्ट्रेलिया के साथ भारत को भी सामरिक दृष्टि से मजबूत बनाना अमेरिका की रणनीति का हिस्सा है।

चीन ने बाकायदा एक बयान जारी कर यह कहा है कि अमेरिका क्वाड के जरिए एशियन नाटो बना रहा है। क्वाड का मुख्य उद्देश्य ही इंडो पैसेफिक क्षेत्र में चीन के वर्चस्व को चुनौती देना है। चीन के पास इस समय 2,566 लड़ाकू विमान हैं, जबकि भारत के पास उसके आधे भी नहीं है। भारत बाहर से लड़ाकू विमानों को खरीद कर इस खाई को पाट नहीं सकेगा। केवल हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड ही उत्पादन बढ़ाकर वायु सेना की जरूरतों को पूरा कर सकता है। प्रधानमंत्री मोदी ने अपनी इस अमेरिका यात्रा में बाइडेन प्रशासन से यह करार कर लिया है कि जनरल इलेक्ट्रिक न सिर्फ भारत में फाइटर जेट का इंजन बनाने का कारखाना लगाएगी, बल्कि तकनीकी हस्तांतरण भी करेगी। इससे स्वदेशी फाइटर जेट तेजस मार्क 2 के उत्पादन में गुणात्मक तेजी आएगी।

हमारे उन नवयुवकों के लिए इससे बड़ी राहत नहीं हो सकती, जो अमेरिका में जाकर नौकरी करना चाहते हैं, लेकिन एच–वन वीजा की कठिन प्रक्रिया के कारण एक निश्चित समयावधि के बाद अमेरिका छोड़ना पड़ता है। अब उन्हें वहां रहते ही वीजा अवधि का समय विस्तार हो जाएगा। निश्चित रूप से अमेरिकी प्रशासन ने इसमें उदारता दिखाई है। पर इसके पीछे उनकी अपनी भी जरूरतें हैं। इस समय भारत के लगभग 40 लाख लोग वहां रह रहे हैं, जो लगभग सभी क्षेत्रों में अपनी सेवाएं दे रहे हैं। स्पेस से लेकर रिटेल व्यवसाय तक में भारतीय सक्रिय हैं और वे अमेरिकी अर्थव्यवस्था में भी बड़ा योगदान कर रहे हैं। यह सुखद आश्चर्य है कि अमेरिका में भारतीय लोगों की जनसंख्या में भले ही एक प्रतिशत है, लेकिन उनके कुल कर संग्रह में भारतीय 6 प्रतिशत से अधिक का योगदान करते हैं। यही स्थिति अमेरिका जाकर पढ़ने वाले भारतीय छात्रों की है। अकेले 2023 के सत्र में अमेरिका सवा लाख भारतीय छात्रों को पढ़ाई का वीजा दे चुका है। भारत का हर छात्र पढ़ाई के एवज में 20 हजार से लेकर 60 हजार डॉलर तक अमेरिका में निवेश कर रहा है।

आज दुनिया आश्चर्य कर रही है कि आखिर प्रधानमंत्री मोदी में ऐसा क्या है कि बाइडेन उनका इस तरह से रेड कार्पेट वेलकम कर रहे हैं।

आज दुनिया आश्चर्य कर रही है कि आखिर प्रधानमंत्री मोदी में ऐसा क्या है कि बाइडेन उनका इस तरह से रेड कार्पेट वेलकम कर रहे हैं। बीबीसी न्यूज ने अपने एक लेख में कहा है कि – वर्तमान वैश्विक आर्थिक और भूराजनीतिक परिस्थितियों में भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अमेरिका यात्रा बहुत महत्वपूर्ण हो गई है। यह स्वागत उस नेता के लिए है जिसे एक बार मानवाधिकार के मुद्दे पर अमेरिका की यात्रा के लिए वीजा देने से इंकार कर दिया गया था। पर अब अमेरिका प्रधानमंत्री मोदी को एक महत्वपूर्ण भागीदार के रूप में देखता है।

बीबीसी का भी मानना है कि अधिकांश देश विनिर्माण के लिए चीन का विकल्प चाहते हैं, और भारत के पास बढ़ते मध्यम वर्ग के साथ एक बड़ा बाजार भी है। दुनिया भारत को चीन प्लस वन नीति के तहत देखना चाहती है। वाशिंगटन में विल्सन सेंटर थिंक–टैंक में दक्षिण एशिया संस्थान के निदेशक माइकल कुगेलमैन का कहना है कि अमेरिका और भारत ने अब व्यापक इंडो–पैसिफिक थिएटर पर आंखें मिलाकर देखना शुरू कर दिया है।

यह प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व की कुशलता और नीतियों में भारत की स्थिरता का प्रभाव है कि अमेरिकी स्वागत सत्कार तथा रक्षा एवं व्यापार में तमाम संभावनाओं के बावजूद भारत ने अपने अन्य सहयोगियों के प्रति दृष्टिकोण में किसी बदलाव का संकेत नहीं दिया है। प्रधानमंत्री मोदी न केवल रूस यूक्रेन युद्ध को बातचीत से हल करने के अपने स्टैंड पर कायम रहे, बल्कि मॉस्को और कीव पर भी कोई टीका टिप्पणी नहीं की।

स्वाभाविक है दोनों देशों के अपने हित हैं जिससे दोनों ही समझौता नहीं करना चाहते। फिर भी तकनीकी, उत्पादन, सेवा और रक्षा उपकरण के क्षेत्र में दोनों की भागीदारी के लिए इक्कीसवीं सदी का खुला मैदान दोनों के सामने है। सधे कदमों से आगे बढ़ते हुए दोनों दूर तक तो साथ जा ही सकते हैं। भारत और अमेरिका के बीच संबंधों की ऊंचाई का नया पड़ाव इसी साल सितंबर में तब आएगा, जब जी–20 राष्ट्राध्यक्षों की बैठक में भाग लेने अमेरिकी राष्ट्रपति बाइडेन नई दिल्ली आएंगे। ❑❑

मणिपुर में हिंसा

तबाही की तह में ड्रग्स माफिया और घुसपैठिए

पूर्वोत्तर के खूबसूरत पहाड़ी राज्यों में शुमार मणिपुर इन दिनों जल रहा है। पहाड़ और मैदान के बीच छिड़ी जातीय जंग में डेढ़ सौ से अधिक जिंदगियां हलाक हो चुकी है। केंद्र की सरकार ने मणिपुर की राज्यपाल अनुसुइया उइके की अगुवाई में शांति कमेटी का गठन और फिर गृहमंत्री अमित शाह की अगुवाई में सर्वदलीय बैठक कर अमन चैन कायम करने की कोशिश की है। राज्य में शीघ्र शांति बहाली के लिए कमोबेश सभी राजनीतिक दल समस्या का हल राजनीतिक तरीके से ही निकलने की बात कह रहे हैं लेकिन अंदरखाने अपनी–अपनी राजनीति कर रहे हैं। मोटेतौर पर हिंसा के लिए इतिहासवाद, राष्ट्रवाद, संप्रदायवाद, जातिवाद, उग्रवाद, मेइती समाज को एसटी के तहत आरक्षण, भू–कानून में परिवर्तन, संरक्षित वन में भूमि सर्वेक्षण और यहां तक की पूर्वोत्तर के बारूद पर हिंदुत्व की माचिस आदि का नारा बुलंद किया जा रहा है, पर असली कारण हथियार, घुसपैठ और मादक द्रव्यों की तस्करी पर एक तरह से ध्यान भटकाया जा रहा है। दरअसल मणिपुर में चल रहे फसाद के पीछे धड़ल्ले से हो रही अफीम की खेती, अवैध हथियार और घुसपैठिए प्रमुख कारण रहे हैं।

लगभग 140 करोड़ की आबादी वाले भारत देश में लाइसेंसी हथियारों की संख्या 36 लाख से कुछ अधिक की है, लेकिन कुल मिलाकर 28 लाख की आबादी वाले मणिपुर में 30 हजार लाइसेंसी हथियार हैं। यानी हर 93 आदमी में से एक के पास लाइसेंसी हथियार है। वही यहां के विभिन्न समूहों के पास भारी तादाद में नाजायज हथियारों का जखीरा उपलब्ध है। पूर्वोत्तर के अन्य राज्यों में लाइसेंसी हथियारों की संख्या देखें तो असम में 19,617, मेघालय में 20,000, मिजोरम में 16,000, सिक्किम में 2,500 और त्रिपुरा में करीब 400 लाइसेंसी हथियार हैं। सरकारी आंकड़ों के मुताबिक देश में हर साल लगभग 80 हजार से एक लाख तक अवैध हथियारों की बरामदगी होती रहती है। अवैध हथियारों से ही देश में 98 प्रतिशत अपराध कारित होते हैं। प्रमाण मिले हैं कि मणिपुर में हालिया मारकाट अवैध

मणिपुर में जारी जातीय हिंसा के पीछे हथियार, घुसपैठ और ड्रग्स की तस्करी के तिकड़ी की अहम भूमिका है। अंतरराष्ट्रीय सीमा से लगे होने के कारण जांच एजेंसियों को और अधिक चौकन्ना होते हुए इस सिंडिकेट को काबू करना होगा।

– अनिल तिवारी

हथियारों से ही हो रही है। खुफिया एजेंसियां पहले से जानती हैं कि मणिपुरके अधिकतर उग्रवादी समूहों के पास राज्य पुलिस से अच्छे हथियार हैं, पर कभी अवैध हथियारों के खिलाफ मुहिम नहीं चली। केंद्रीय गृहमंत्री ने अपने राज्य के हालिया दौरे के दौरान लोगों से हथियार जमा करने की अपील की तो कुल जमा 140 लोग हथियार सरेंडर करने के लिए आगे आए। इनमें एकके–47, इसाम्स राइफल, लाइट मशीन गन, पिस्तौल, एम–16 राइफल, आंसू गैस के गोले से लेकर ग्रेनेड तक शामिल थे। मालूम हो कि हिंसा भड़कने के बाद 20 पुलिस स्टेशनों को जलाने के साथ दो चरणों में पुलिस के हथियार लूट लिए गए। पुलिस द्वारा दर्ज की गई प्राथमिकी के अनुसार 3 मई को 1600 तथा 27 और 28 मई को 2557 हथियार लूटे गए।

जहां तक मणिपुर में घुसपैठियों का सवाल है तो इसकी शुरुआत ब्रिटिश काल में ही हुई थी। अंग्रेजों ने स्वभाव से शिकारी, युद्ध कला में निपुण और हेड हंटर्स नागाओं तक अपनी पैठ बनाने के लिए सीमा पार से लड़ाकू कौम 'न्यू कुकी' समुदाय के लोगों को यहां बसाना शुरू किया। अंग्रेज इनका इस्तेमाल नागा क्षेत्रों में छापा मारने और वसूली करने के लिए करते थे। धीरे–धीरे वे यहां की जमीन पर बसते गए, फैलते गए। इनका इतिहास काफी रक्तरंजित रहा है। दिसंबर 1892 की घटना मणिपुर के इतिहास में दर्ज है, जब न्यू कुकियों ने मणिपुर नागालैंड बॉर्डर पर स्थित नागा गांव चिंगजराई में भयानक नरसंहार किया था। मणिपुर में घुसपैठ की समस्या को इन आंकड़ों के जरिए समझा जा सकता है। 1969 के बाद पहाड़ी क्षेत्रों में गांव की संख्या 64 प्रतिशत तक बढ़ी है। जैसे पहले कुकी नगा बहुल क्षेत्रों में 1370 गांव थे, जो 2021 में बढ़कर 2244 हो गए हैं। म्यांमार से सटे जिला चुराचांदपुर की बात करें तो यहां 1969 में 282 गांव थे जो 2022 में 544 हो गए हैं। मणिपुर से म्यांमार के बीच करीब 390 किलोमीटर अंतरराष्ट्रीय सीमा लगी हुई है। खुफिया जानकारी के मुताबिक ज्यादातर घुसपैठ म्यांमार बॉर्डर से हो रही है।

सिर्फ अफीम की तस्करी से हर महीने दो हजार करोड से ज्यादा की कमाई हो रही है, जो भारत के कई छोटे राज्यों के सालाना बजट से भी ज्यादा है। अफीम के मामले में मणिपुर पड़ोसी देश म्यांमार के रास्ते पर है। पिछले कुछ वर्षों तक म्यामार दुनिया की 80 फीसद अफीम से बनी हीरोइन का उत्पादन करता था। उत्पादन के बाद हीरोइन की तस्करी लाओस, वियतनाम, थाईलैंड और भारत के रास्ते अमेरिका, ब्रिटेन और चीन में की जाती रही है।

जांच एजेंसियों के मुताबिक भारी मात्रा में हथियारों के साथ घुसपैठ करके आए तमाम विद्रोही संगठनों की नजर राज्य में होने वाली अफीम की खेती पर है। वर्ष 2016 से ही मणिपुर में संरक्षित वन क्षेत्र की सफाई कर धड़ल्ले से अफीम की खेती हो रही है। इससे जनजातीय किसानों की आय तो बढी है, पर नशे के सौदागरों की भी चांदी हो गई है। नशे के कारोबार से हो रही कमाई के कारण आज उनके पास जमीनें हैं, देश विदेश के विद्रोही संगठनों और नशे के सौदागरों से मेलजोल है, अच्छा पैसा है, आधुनिक हथियार है, राजनीति में दखल और पावर सहित सब कुछ है। वर्ष 1992–93 में हुए नागा–कुकी संघर्ष के बाद कुकी लोगों ने अलग कुकीलैंड बनाने की मांग भी की थी।

आधिकारिक आंकड़ों के मुताबिक सिर्फ अफीम की तस्करी से हर महीने दो हजार करोड से ज्यादा की कमाई हो रही है, जो भारत के कई छोटे राज्यों के सालाना बजट से भी ज्यादा है। अफीम के मामले में मणिपुर पड़ोसी देश म्यांमार के रास्ते पर है। पिछले कुछ वर्षों तक म्यामार दुनिया की 80 फीसद अफीम से बनी हीरोइन का उत्पादन करता था। उत्पादन के बाद हीरोइन की तस्करी लाओस, वियतनाम, थाईलैंड और भारत के रास्ते अमेरिका, ब्रिटेन और चीन में की जाती रही है। म्यांमार में सिविल वार के बाद हालात बदल गए हैं। इसलिए नशे के कारोबारियों की नजर मणिपुर की विशाल जनजातीय भूमि पर है। इस काम में विभिन्न राजनीतिक दलों का शह पाकर विद्रोही संगठन भी अपना उल्लू सीधा कर रहे हैं। हालांकि मामले की गंभीरता को भांपते हुए सरकार अफीम की खेती पर अंकुश लगाने के लिए ठोस कदम उठा रही है। इसके सकारात्मक परिणाम भी दिख रहे हैं। सरकारी आंकड़े के मुताबिक वर्ष 2017–18 में जहां 13121 एकड़ भूखंड पर मणिपुर में अफीम की खेती हुआ करती थी, लेकिन वर्ष 2022 में सरकारी अभियान के बाद अफीम की खेती का रकबा घटकर 2340 एकड़ तक आ गया है।

ऐसे में कुल मिलाकर कहा जा सकता है कि मणिपुर में जारी जातीय हिंसा के पीछे हथियार, घुसपैठ और ड्रग्स की तस्करी के तिकड़ी की भी अहम भूमिका है। अंतरराष्ट्रीय सीमा से लगे होने के कारण जांच एजेंसियों को और अधिक चौकन्ना होते हुए इस सिंडिकेट को काबू करना होगा। ❑❑

यूसीसीः सभी के लिए नागरिक उपचार

समान नागरिक संहिता की अवधारणा पर भारत में दशकों से बहस चल रही है। कुछ राजनितिक दलों के अनुसार यह समानता और पंथनिरपेक्षता को बढावा देगा वहीं विरोधियों का तर्क है कि यह धार्मिक स्वतंत्रता एवम सांस्कृतिक अभ्यासों में हस्तक्षेप करेगा। समान नागरिक संहिता का उल्लेख भारतीय संविधान के अनुच्छेद 44 में राज्य के नीति निर्देशक तत्व में किया गया है। इसके अनुसार राज्य पूरे भारत में नागरिकों के लिए एक समान नागरिक संहिता सुनिश्चित करने का प्रयास करेगा।

कोई भी समझदार व्यक्ति इस बात से इंकार नहीं कर सकता कि भारत जैसे विविधता पूर्ण देश में समान नागरिक संहिता का होना अनिवार्य है ताकि एक सभ्य नागरिक समाज में विवाह तलाक संपत्ति में अधिकार विरासत गोद लेने जैसे गंभीर विषयों पर बिना किसी धार्मिक जातिगत भेदभाव के समान कानून बन सके। परंतु भारत में विभिन्न समुदायों के हित एवं विचारों की बहुलता के कारण यूसीसी आज तक लागू नहीं हो पाया। भारतीय जनता पार्टी ने अपने चुनावी वादों में तीन प्रमुख वादे किए थे, जैसे राम मंदिर का निर्माण, धारा 370 को निरस्त करना और समान नागरिक संहिता। भारतीय जनता पार्टी दो वादे अब तक पूरा कर चुकी है और अब अपने तीसरे वादे को कानूनी रूप देने की तैयारी में जुटी है, किंतु इसी बीच कुछ राजनीतिक दल और लोग इसका विरोध कर रहे हैं कि बहुसंख्यक समाज बनाने की तैयारी है जिसमें अल्पसंख्यकों के हितों को खतरा होगा और धार्मिक समुदायों के रीति रिवाज और उनकी पहचान नष्ट हो जाएगी। लेकिन यह आरोप पूरी तरह गलत और पथ भ्रमित है।

सुप्रीम कोर्ट ने कई बार अपने फैसलों में समान नागरिक संहिता के विचार को समर्थन दिया लेकिन न्यायालय बार–बार यह भी कहता रहा है कि यूसीसी केवल तभी प्रभावी हो सकता है जब सारे राजनीतिक दल और राजनेता अपने व्यक्तिगत लाभ से ऊपर उठकर समाज में समानतापूर्ण परिवर्तन स्वीकार करेंगे।

– डॉ. जया कक्कड़

संविधान के अनुसार हमारा भारत एक धर्मनिरपेक्ष देश है, इसलिए समान नागरिक संहिता का इस देश में लागू होना जरूरी है, ताकि सभी धार्मिक समूहों के व्यक्तिगत कानून को एक समान तरीके से नियंत्रित किया जा सके। भारत के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने 1950 में हिंदू पर्सनल लॉ में सुधार किया था क्योंकि संविधान सभा में भी इस बात पर बहस हुई थी कि व्यक्तिगत कानूनों में कमियां है, जिससे समानता और न्याय जैसे सिद्धांत की अवहेलना होती है। इसलिए समान नागरिक संहिता को उसी समय पूरे देश में लागू करने की दिशा में काम करना चाहिए था परंतु यह काम आजादी के इतने सालों बाद मोदी सरकार के नेतृत्व में किया जा रहा है और इस फैसले का हमें स्वागत करना चाहिए।

आज भारत में खुद को धर्मनिरपेक्ष कहने वाले अधिकांश राजनीतिक दल इस मुद्दे से अपना पाला छुड़ा रहे हैं और भरपूर विरोध कर रहे हैं। ऐसा इसलिए है क्योंकि कांग्रेस और कम्युनिस्ट पार्टियां अल्पसंख्यक वर्गों को खुश करने और मुस्लिम वोट बैंक की राजनीति करती आई है। ऐसे में जो मुसलमान अपने पारंपरिक कानूनों में बदलाव करना भी चाहते हैं उनकी मांगों को भी यह पार्टियां नकारती हैं ताकि कट्टर मौलवियों द्वारा मुस्लिम वोट बैंक की राजनीति चलती रहे। हालांकि इस प्रक्रिया में सबसे ज्यादा नुकसान मुस्लिम महिलाओं का ही होगा। हमें नहीं भूलना चाहिए कि भारत एक धर्मनिरपेक्ष देश है, जो किसी भी प्रकार के धार्मिक भेदभाव की अनुमति नहीं देता। ऐसे में समान नागरिक

संहिता की मांग और प्रबल हो जाती है।

बीते दिनों उत्तराखंड में समान नागरिक संहिता पर गठित कमेटी ने राज्य के लिए यूसीसी के मसौदे को सार्वजनिक कर दिया। इस ड्राफ्ट को तैयार करने के लिए अन्य देशों में बने पारिवारिक कानूनों पर भी अध्ययन किया गया है। मसौदा समिति की प्रमुख न्यायमूर्ति रंजना देसाई के अनुसार यह राज्य में धर्मनिरपेक्ष के सिद्धांत को मजबूत करेगा इस मसौदे में लड़कियों के लिए विवाह योग्य आयु बढ़ाने, लिव इन रिलेशनशिप को वैध बनाने, विरासत संबंधी कानून ,बहुविवाह और बहुपति जैसी प्रथा पर रोक लगाने के प्रस्ताव शामिल हैं। बहुत सारे प्रस्तावों जैसे लड़कियों के विवाह योग्य आयु बढ़ाने का उद्देश्य महिला के अधिकारों को संरक्षित करेगा और नारी सशक्तिकरण को सुनिश्चित करेगा। बहुत सारे धार्मिक प्रथाओं के रुढ़िवादी अभ्यासकर्ता इसको गलत कहेंगे ताकि महिलाओं की प्रगति को रोका जा सके। धार्मिक आस्था के नाम पर ऐसे लोग कमजोर वर्गों के विकास पर अपनी नाराजगी जताएंगे लेकिन हमें समझना होगा कि अनुच्छेद 44 को असल मायने में लागू करने का समय आ गया है। हमें इसका पूरे दिल से समर्थन करना चाहिए। परंतु इस गंभीर विषय पर तर्कसंगत चर्चा की भी जरूरत है ताकि यूसीसी का राजनीतिकरण न हो।

यूसीसी के खिलाफ यह तर्क दिया जाता है कि इससे पारंपरिक मान्यताओं को त्यागना पड़ेगा, लेकिन बहुत विडंबना है कि हम उन सभी प्रथा का पालन क्यों करें जो असल मायने में अमानवीय है और क्रूरता से भरी है। जैसे हिंदुओ में (सती प्रथा कन्या भ्रुण हत्या आदि) इसी तरह मध्यकाल तक सरिया व्यक्तिगत कानून और मुसलमानों के अपराधिक कानून दोनों को नियंत्रित करता था। इस कानून के तहत चोरी की सजा, चोर की उंगलियां काटने की थी, और व्यभिचार के लिए किसी व्यक्ति को पत्थर मारकर मौत की सजा दी जाती थी । आज हम एक सभ्य समाज में रहते हैं जहां सबके लिए एक समान अपराधिक कानून है जहां ऐसी बर्बर प्रथाओं को कोई स्थान नहीं है। हम क्यों नहीं सब घृणित परंपराओं का त्यागकर देते और एक समान नागरिक संहिता का समर्थन करते जो प्रत्येक जीवित प्राणी पुरुष महिला या किसी भी यौन अभिविन्यास और किसी भी धर्म के लिए उच्च, समान उपचार सुनिश्चित करती है?

यूसीसी की बहस का एक लंबा इतिहास है लेकिन इसका मूल सिर्फ इतना है कि किसी भी देश में सभी नागरिकों को शासित करने के लिए एक ही नागरिक संहिता हो जैसे भारत में सभी नागरिक एक ही अपराधिक संहिता द्वारा शासित होते हैं।

1950 के दशक के मध्य में तत्कालीन कांग्रेस सरकार ने विवाह, तलाक और संपत्ति के उत्तराधिकार के हिंदू कानूनों में बदलाव किए लेकिन वह अन्य धार्मिक कानूनों में समान सुधार नहीं ला पाई। इसकी प्रमुख वजह मुस्लिम वोटों को संरक्षित करना था। बाद में यह कहकर यूसीसी को टाला गया कि भारत अपने अल्पसंख्यकों के प्रति जिम्मेवार है और बहुसंख्यकवादी राज्य नहीं बनना चाहता। लेकिन सवाल यह है कि आज दुनिया में बहुत सारे देश है (जैसे– ब्रिटेन, अमेरिका आदि) जहां रहने वाले लाखों मुसलमान समान नागरिक संहिता का पालन करते हैं और अलग व्यक्तिगत कानून के लिए आंदोलन नहीं करते तो भारत में समान नागरिक संहिता क्यों नहीं? हमारा संविधान जाति लिंग धर्म और जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव पर रोक लगाता है। ऐसे में सिर्फ यूसीसी ही असल मायने में सभी हिंदू मुस्लिम सिख इसाई पारसी की धार्मिक भेदभाव वाली प्रथाओं का अंत कर सकता है। गोवा की आजादी से पहले वहां पुर्तगालियों का शासन था जिसने सत्ता में रहते हुए पुर्तगाली कोड लागू किया था जो एक समान नागरिक संहिता है। यदि उस समय मुसलमानों ने विरासत और संपत्ति के अधिकार में ऐसे कानूनों को स्वीकार कर लिया तो आज भारत के अन्य राज्यों में क्यों नहीं कर सकते?

हमें यह समझना होगा कि यूसीसी सिर्फ मुसलमानों को प्रभावित नहीं करता बल्कि इसका असर हिंदू बहुसंख्यक और अन्य सभी धर्मों के लोगों पर समान रूप से पड़ेगा परंतु हमारा लक्ष्य लैंगिक समानता और न्याय सुनिश्चित करना है। इसलिए हमें उन सभी प्रथाओं का त्याग करना होगा जो भेदभाव पूर्ण है और सदियों से हमारी धार्मिक परंपराओं में मौजूद है। वर्तमान में दो कारकों ने यूसीसी को राजनीतिक रंग दे दिया है। पहला हिंदुत्व की राजनीति के साथ भाजपा का जुड़ाव और रूढ़िवादी मुस्लिम समुदायों में सुधार के प्रति विरोध। लेकिन यह एक गंभीर विषय है जिसके कई संवैधानिक, कानूनी, सामाजिक राजनीतिक और आर्थिक प्रभाव होंगे जो सभी नागरिकों को प्रभावित करेंगे। अब स्थिति यह है कि बैल को उसके सींग से पकड़ना होगा, कोई और विकल्प नहीं है। अनुच्छेद 44 राज्य के नीति निर्देशक तत्व के रूप में हमारे लिए एक प्रेरणा है कि समाज में नागरिक संहिता लागू होनी चाहिए। यह हमारे संविधान निर्माता द्वारा हमारे लिए एक मार्गदर्शक है जिसे लागू करना राज्य के हाथ में है। इसलिए सुप्रीम कोर्ट ने कई बार अपने फैसलों में समान नागरिक संहिता के विचार को समर्थन दिया लेकिन न्यायालय बार–बार यह भी कहता रहा है कि यूसीसी केवल तभी प्रभावी हो सकता है जब सारे राजनीतिक दल और राजनेता अपने व्यक्तिगत लाभ से ऊपर उठकर समाज में समानतापूर्ण परिवर्तन स्वीकार करेंगे। ❑❑

वस्तु एवं सेवा करः छोटे को बड़े के साथ समान अवसर प्रदान करना

भारत के सबसे क्रांतिकारी कर सुधारों में से एक वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) केंद्र और राज्य द्वारा एकत्र किए गए कई अप्रत्यक्ष करों को खत्म करने के लिए डिजाइन किया गया है। वस्तु एवं सेवा कर लागू होने से देश भर में समान कीमत, सरलीकृत प्रणाली, विदेशी निवेश, आयात और निर्यात उद्योग में वृद्धि, पारदर्शिता, आसान उधारी, कई करों का एकीकरण, कर चोरी की जांच के साथ–साथ बाजार में मौजूद बड़े खिलाड़ियों के साथ प्रतिस्पर्धा करने वाले छोटे खिलाड़ियों को भी समान अवसर प्राप्त हुआ है।

किसी भी क्षेत्र का एक बड़ा खिलाड़ी अपने आपूर्ति श्रृंखला प्रथाओं को जिस तरह आगे एकीकृत करता है ठीक उसी तरह पीछे भी एकीकृत किया जा सकता है। जब कोई कंपनी आगे एकीकृत कर रही होती है तो वह अपने नियोजित उत्पाद को अपने सिस्टम पर अंतिम उपयोगकर्ता ग्राहक के करीब ले जा रही होती है और इस प्रकार संपूर्ण अग्रसारित आपूर्ति श्रृंखला पर नियंत्रण रखती है। जब कोई कंपनी खुद को पीछे की ओर एकीकृत कर रही होती है तो वह नियोजित उत्पाद का उत्पादन करने के लिए आवश्यक कच्चे माल और अन्य सहायक भागों की आपूर्ति को नियंत्रित करने का प्रयास कर रही होती है। पीछे एकीकृत को समझने के लिए उदाहरण स्वरूप यदि हम एक ऐसी कंपनी का विचार करते हैं जो आलू के चिप्स का निर्माण कर रही है, तो यह कंपनी आलू की मालिक है।आलू का मालिक होने के लिए कंपनी ट्रकों सहित लॉजिस्टिक नेटवर्क की भी मालिक है। कंपनी कोल्ड स्टोरेज सुविधाओं की भी मालिक है। आलू की खेती करने वाले किसानों के करीब रहकर अपना उद्योग आगे बढ़ाने में लगी है कंपनी किसानों के साथ कानूनी रूप से बाध्य कृषि अनुबंध करती है या भूमि मालिकों से लंबे समय के लिए कृषि भूमि पट्टे पर भी ले लेती है।इस मामले में आगे के एकीकृत का मतलब है कि कंपनी के पास पैक किए गए आलू के चिप्स को बाजार तक पहुंचाने के लिए लॉजिस्टिक सुविधा है इसके पास बाजार के पास से गोदाम भी है इसके आलू के चिप्स के लिए विशेष हो और विशेष खुदरा दुकानें भी हैं साथ ही साथ यह अन्य आलू चिप्स निर्माता द्वारा तैयार किए गए यथासंभव ग्राहकों के निकट भी है। इस परिदृश्य में कंपनी के पास सब कुछ उपलब्ध है और इसलिए कंपनी द्वारा भुगतान किया गया कर भी उसकी जानकारी में है। कंपनी अपने पिछले और आगे की आपूर्ति श्रृंखला का पता लगा सकती है और अपनी परिचालन दक्षता में सुधार कर सकती है और इस प्रकार कुल लाभ मार्जिन में लगातार वृद्धि भी कर सकती है।

जबकि दूसरी तरफ एक छोटा खिलाड़ी जो आलू के चिप्स बनाता है वह दूसरे छोटे खिलाड़ियों पर निर्भर होता है। एक छोटा खिलाड़ी आलू की आपूर्ति करता है, एक अन्य छोटा खिलाड़ी है जो चिप्स को बाजार तक पहुंचाता है और एक अन्य छोटा दुकान विक्रेता

जीएसटी ने संगठित क्षेत्र का आधार विस्तृत किया है और छोटे व्यवसाय को संगठित प्रणाली में शामिल होने के लिए प्रेरित भी किया। जीएसटी लागू होने से पारदर्शिता बढ़ी है और विस्तार प्रक्रिया में किसी भी हितधारक के शोषण को बहुत हद तक नियंत्रित किया है।

–आलोक सिंह

है जो आलू के चिप्स बेचता है। इस तरह छोटे आलू चिप्स व्यवसाय में खेत से लेकर अंतिम उपयोगकर्ता ग्राहक तक छोटे खिलाड़ियों की एक बड़ी श्रृंखला हो सकती है।

ऐसे में जीएसटी प्रभात प्रणाली के अभाव में छोटे खिलाड़ी की उत्पादन लागत अधिक होगी और इसलिए उसकी बाजार हिस्सेदारी छोटी होती जाएगी। ऐसे खिलाड़ियों को स्थिरता की रोशनी आसानी से नहीं मिल पाती और वे जीवन भर अस्तित्व के लिए संघर्ष करते रहते हैं। पुरानी कर प्रणाली ऐसी थी कि छोटे खिलाड़ियों को कर का भुगतान नहीं करना पड़ता था और बड़े एकीकृत खिलाड़ियों के साथ उत्पादन लागत के मिलान के लिए सुविधाओं तक पहुंच भी नहीं मिलती थी। इसका मतलब यह है कि छोटे खिलाड़ियों द्वारा कर से बचाव उच्च उत्पादन लागत, कम बाजार हिस्सेदारी और इसीलिए कम लाभ की मार्जिन की कीमत पर होता था। ऐसे में किसी एक मुकाम पर किन्ही कारणों से मिली विफलता छोटे व्यवसाई को आसानी से व्यवसाय से बाहर कर सकती है। जीएसटी की यही खूबी है कि इसने छोटे खिलाड़ियों के लिए बड़े खिलाड़ियों के साथ समान बाजार व्यवहार करने का अवसर प्रदान किया है।

राज्य और केंद्रीय करों की पुरानी प्रणाली के व्यापक प्रभाव से छोटे व्यवसाय पर प्रतिकूल असर पड़ा था। जीएसटी में इनपुट टैक्स क्रेडिट तंत्र छोटे व्यवसाय को बड़े एकीकृत व्यवसायियों के साथ उत्पादन की लागत का मिलान करने का अवसर प्रदान करता है। पहले बड़े एकीकृत व्यवसाय कच्चे माल, लॉजिस्टिक, समर्थन, बाजार पहुंच और अन्य कार्यों को घर में ही प्राप्त कर सकते थे जबकि छोटे व्यवसाय उसी कच्चे माल लॉजिस्टिक समर्थन बाजार पहुंच और अन्य कार्यों के लिए बाहरी एजेंसियों पर निर्भर थे। जिसके परिणाम स्वरूप बड़े एकीकृत व्यवसाय की तुलना में छोटे व्यवसायों के लिए उत्पादन संचालन और लागत अधिक होती थी। जीएसटी लागू होने से छोटे व्यवसाय को मुनाफा कमाने के लिए संगठित तंत्र को एक तरह से दरकिनार किया गया और ऐसे व्यवसाय अपने अस्तित्व के लिए ज्यादातर कठिन मुद्रा से ही निपटते थे। वह छोटा व्यवसाय जिसने सफलता का एक स्थाई स्तर प्राप्त कर लिया है वह लाभ कमाने के लिए कठिन मुद्रा लेनदेन तंत्र पर भी भरोसा कर सकता है। फिर भी संगठित जैसा इसे इस तरह के जानबूझकर किए गए बहिष्कार से दक्षता उत्पादकता और कई अन्य चीजों में भारी बदलाव आया है। एक बार जब कोई छोटा व्यवसाय जीवित रहता है तो वही स्थिरता की आकांक्षा करता है और फिर बाजार में अपनी पहुंच का विस्तार करके लाभ को अधिकतम करने का लक्ष्य निर्धारित करता है। ऐसे व्यवसाय कर चोरी के माहिर होते थे, जीएसटी व्यवस्था ने ऐसे व्यवसायियों को लाइन में लगने के लिए मजबूर कर दिया है।

जीएसटी के साथ–साथ केंद्र सरकार छोटे संगठित व्यवसायियों को संगठित, व्यवसाय की ओर स्थानांतरित करने के लिए प्रोत्साहन की योजनाएं भी लेकर आई है। उत्पादन से जुड़ा प्रोत्साहन, (पीएलआई) कर अवकाश अवधि, ईकॉमर्स को विनियमित करने, ओपन नेटवर्क डिजिटल कॉमर्स (ओएनडीसी) प्रदान करने जैसे कई अन्य आश्वासनों और कार्यों के संदर्भ में सहायता जैसी योजनाएं शामिल है। जाहिर तौर पर जीएसटी तंत्र छोटे व्यवसायों के लिए एक बड़ी राहत है। इसके अतिरिक्त असंगठित क्षेत्र में छोटे व्यवसायियों के लिए रीढ़ की लागत असंगठित क्षेत्र की तुलना में सस्ती है। छोटे व्यवसाय के लिए असंगठित क्षेत्र या अनौपचारिक श्रेणी में बने रहने के लिए कोई प्रेरणा नहीं बची है, क्योंकि संगठित श्रेणी में छोटे व्यवसाय को दी जाने वाली पारदर्शिता जवाबदेही और सुविधाएं बहुत बड़ी है। जीएसटी असंगठित श्रेणी के व्यवसाय को संगठित श्रेणी में बदलने के लिए एक ट्रिगर बिंदु है। ऐसे में छोटे व्यवसाय एक साथ आ सकते हैं। अपने उत्पादों और सेवाओं के लिए एक अलग कलस्टर बना सकते हैं और अपने व्यवसाय के लिए एक सहकारी समिति भी खड़ा कर सकते हैं। लेकिन यह तभी संभव है जब किसी विशेष उत्पाद या सेवा के सभी छोटे व्यवसाय संगठित रूप से जुड़े।

देश में पेट्रोलियम उत्पाद फिलहाल जीएसटी के दायरे से बाहर है। पेट्रोलियम उत्पाद, रसद और परिवहन लागत को बड़े पैमाने पर प्रभावित करते हैं। पेट्रोलियम उत्पादों को जीएसटी में शामिल करने से छोटे व्यवसाय को और अधिक मदद मिलेगी। इसी तरह रियल स्टेट व्यवसाय मुख्य रूप से असंगठित है और बड़े शहरों के कई छोटे ठेकेदार और छोटे शहरों के बड़े ठेकेदार हैं जो असंगठित क्षेत्र में व्यवसाय करने में सहज है। रियल स्टेट का क्षेत्र जीएसटी के दायरे में है लेकिन रियल स्टेट क्षेत्र में जीएसटी के बारे में कई किंतु–परंतु है। सरकार को रियल स्टेट के लिए एक सरल जीएसटी तंत्र विकसित करना चाहिए जो रियल एस्टेट खरीददारों, डेवलपर्स और रियल स्टेट परियोजना आपूर्ति श्रृंखला के सदस्यों द्वारा समझने योग्य और व्याख्या करने योग्य भी हो। कुल मिलाकर जीएसटी ने संगठित क्षेत्र का आधार विस्तृत किया है और छोटे व्यवसाय को संगठित प्रणाली में शामिल होने के लिए प्रेरित भी किया। जीएसटी लागू होने से पारदर्शिता बढ़ी है और विस्तार प्रक्रिया में किसी भी हितधारक के शोषण को बहुत हद तक नियंत्रित किया है। ❑❑

(आलोक सिंह भारतीय प्रबंधन संस्थान इंदौर के फेलो एक स्वतंत्र शिक्षाविद है और एजीपी बिजनेस स्कूल झज्जर से संबद्ध है)।

दुराग्रही विदेशी मीडिया
भारत विरोधी प्रचार में जुटी

यह भारत का दुर्भाग्य ही है कि भारत के कुछ प्रमुख राजनेता विदेशों में जाकर भारत के प्रधानमंत्री के प्रति नफरत फैलाने का प्रयास करते रहते है। वहीं कुछ विदेशी मीड़िया भी दुराग्रह से परिपूर्ण होकर भारत विरोधी प्रचार करने में जुटी है। जब से भारतीय जनता पार्टी के नेता नरेन्द्र मोदी ने प्रधानमंत्री पद की शपथ ग्रहण की है तभी से कुछ ज्यादा ही दुष्प्रचार किया जा रहा है, लगता तो ऐसा ही है। देश की विपक्षी राजनीतिक दलों के साथ विदेशी मीड़िया भी विपक्ष की ही भुमिका निभा रही है। कुछ दिन पहले बीबीसी (ब्रिटिश ब्राड़कास्टिंग कॉर्पोरेशन) ने एक ड़ाक्यूमेंट्री बनायी जिसमें भारत के प्रति दुष्प्रचार करने की कोशिश की गई जिसके प्रचार व प्रसार में वामपंथी तथा विपक्षी राजनीतिक दलों ने अपनी सक्रिय भूमिका निभाई तथा कुछ नामचीन विश्वविद्यालयों के प्रागणों में भी पहुंचकर नव–युवकों को भी भारत विरोधी प्रचार में लगा दिया गया थ।

बीबीसी को भारत के पड़ोसी देशों में वहां के गैर मुस्लिम अल्पसंख्यकों पर ड़ाक्यमेंट्री जरुर बनानी चाहिए। बीबीसी को अपना वामपंथी मुखौटा हटाना चाहिए तथा मनुष्य व मानवता को सर्वोच्च स्थान देना चाहिए।

– डॉ. सूर्यप्रकाश अग्रवाल

वर्ष 2002 के गुजरात दंगों पर बीबीसी की ड़ाक्यूमेंट्री 'इंड़िया–द मोदी क्वेश्चन' को भारत ने औपनिवेशिक मानसिकता से प्रेरित और गुमराह करने वाला बताया है। यह भारत विरोधी प्रचार का हिस्सा है। भारत के विदेश मंत्रालय ने इस ड़ाक्यूमेंट्री के जरिये प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की छवि को हानि पहुंचाने की कोशिशों का प्रोपेगंड़ा ही बताया। स्वंय ब्रिटिश प्रधानमंत्री ऋषि सुनक ने ड़ाक्यूमेंट्री के तथ्यों को खारिज कर दिया। सुनक ने ब्रिटेन की ससंद में कहा कि' निश्चित रुप से हम उत्पीड़न बर्दाश्त नहीं करते है, चाहे वह कहीं भी हो, लेकिन मै उस चरित्र चित्रण से कतई सहमत नहीं हूं जो माननीय नेता (पीएम मोदी) का दिखाया गया है। ब्रिटेन के हाउस ऑफ लार्ड़ के सदस्य लार्ड़ रामी रेंजर ने कहा कि बीबीसी ने भारत के करोड़ों लोगों की भावनाओं को आहत किया है और लोकतान्त्रिक रुप से निर्वाचित भारत के प्रधानमंत्री, वहां की पुलिस, और न्यायपालिका की बेइज्जती की है। हम दंगों की निन्दा करते है। तत्कालीन विदेश सचिव कंवल सिब्बल ने कहा कि वर्ष 2002 के दंगों के दौरान ब्रिटेन के उच्चायुक्त की तरफ से भारत के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप करने पर चेतावनी दी गई थी।

बीबीसी ने मोदी सरकार के अल्पसंख्यकों के प्रति रवैये, कथित विवादित नीतियों, कश्मीर के विशेष दर्जे को खत्म करने के फैसले और नागरिकता कानून को लेकर भी सवाल उठाए गए है। बागची ने आगे कहा कि यह दुष्प्रचार का हिस्सा है जो खास तरह के नजरिये को आगे बढ़ाता है। यह पक्षपात पूर्ण होने के साथ ही औपनिवेशिक मानसिकता से प्रेरित

है। बीबीसी ने कहा कि ब्रिटेन के विदेश मंत्रालय से लिए गए गोपनीय कागजातों के आधार पर इस ड़ोक्यूमेंट्री को तैयार किया था। ये गोपनीय कागजात वर्ष 2002 में नई दिल्ली स्थित ब्रिटिश उच्चायोग की तरफ से अपने हेड़क्वाटर को भेजी गई रिपोर्ट से संबधित है। कंवल सिब्बल के अनुसार तब भी उन्हें चेतावनी दी गई थी कि हमारे आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप नहीं करें।

विदेशी मीड़िया का एक हिस्सा भारत के प्रति दुराग्रह से भरा हुआ है। इसी दुराग्रह के कारण बीबीसी ने पत्रकारिता के मूल सिद्धान्तों की अनदेखी कर पश्चिमी देशों के लिए अलग मानदंड़ बनाये हुए है। और बाकी देशों के लिए अलग। वह विकासशील और निर्धन देशों को केवल अपने अलग चश्में से ही देखता है बल्कि उसके नेताओं और वहां की जनता को भी अलग कसौटी पर कसता है जिसका प्रमाण यह ड़ाक्यूमेंट्री है।

बीबीसी को अपनी श्रेष्ठता बोध का अहंकार भी है। बीबीसी की यह पक्षपातपूर्ण रिपोर्टिंग ही कही जा सकती है। बीबीसी ने इस बात को नहीं देखा कि गुजरात दंगों की गहराई से जांच देश के सुप्रीम कोर्ट की निगरानी वाले एक विशेष जांच दल ने की थी। बीबीसी ने दुराग्रह का परित्याग नहीं किया जिससे उसने पक्षपाती विमर्श प्रस्तुत किया। बीबीसी भारत में कोरोना काल में लॉकड़ाउन के दुष्परिणाम ही गिनाती रहती है। जबकि यूरोपीय देशों में उसने लाखों लोंगों की जान बचते हुए देखी। भारत में कोरोना के कारण मरे लोगों के भावों को दिखाता है। पश्चिमी मीड़िया के साथ साथ उसके भाोध संस्थान भी दुराग्रह से ग्रस्त है। गुजरात के दंगे के शुरुआत पर ध्यान क्यों नहीं दिया जाता जिसे गोधरा कांड़ के नाम से जाना जाता है। जिसमें मुस्लिमों की भीड़ ने रेल की एक बोगी को जला दिया था जिसमें 70 कार सेवक जो अयोध्या से लौट रहे थे, वे जिन्दा जला दिये गये थे। उसको तो बीबीसी ने साबरमती एक्सप्रेस में लगी साधारण आग बताकर मात्र एक वाक्य में निपटा दिया गया। इस कांड़ में 31 लोगों को न्यायालय के द्वारा सजा सुनायी गई जिसे गुजरात हाई कोर्ट ने भी स्वीकार किया। मोदी का प्रधानमंत्री बनना पंथनिरेपक्षता के नाम पर छल व मक्कारी के प्रति जन विद्रोह था। इस लिए 2002 की घटना को विमर्श में दोबारा लाना मोदी को नुकसान पंहुचायेगा। यह ड़ाक्यूमेंट्री वैश्विक वामपंथ के निशाने पर मोदी को लाने की एक कोशिश है क्योंकि ब्रिटेन में लेबर पार्टी का वोट बैंक वहां की मुस्लिम आबादी है। अतः उसको भी खुश करना उद्देश्य था। बीबीसी का चरित्र वामपंथी ही कहा जा सकता है। इसी वामपंथी रवैये के कारण बीबीसी ब्रिटेन में भी अपनी विश्वसनीयता खो चुकी है। ब्रिटेन की पूर्व प्रधानमंत्री मार्गरेट थैचर कहती है कि उन्होंने तीन चुनाव लेबर पार्टी के विरुद्ध नहीं बल्कि बीबीसी के विरुद्ध लड़े थे। ड़ाक्यूमेंट्री को लेकर लार्ड डालर पोपट, लार्ड रामी रेंजर इत्यादि बुद्धिजीवियों ने बीबीसी की आलोचना की है। बीबीसी का इतिहास बताता है कि उसको हिन्दू विरोध करने पर शान्ति प्राप्त होती है। 1965, 1971 का भारत पाक युद्व, खालिस्तान आतंकवाद तथा लेस्टर दंगे में स्पष्ट दिखाई दे चुका था। इससे पूर्व बीबीसी की ड़ाक्यूमेंट्री 'इंड़ियाज डाटर' जो 2015 में बनी थी, पर भी विवाद हुआ था। इस ड़ाक्यूमेंट्री में वे हिस्से हटा दिये गये थे जो भारत के अनुपात में पश्चिमी देशों में महिला यौन उत्पीड़न के अधिक आंकड़े को उद्धत करते थे।

वर्ष 2008 में भी मुंबई हमले के आक्रमणकारियों को मात्र गनमैन कहा गया था। इंदिरा गांधी सरकार ने बीबीसी पर प्रतिबंध लगाया था। 1984 के सिख दंगे तथा कश्मीर में 1971 के बाद से हो रहे हिन्दू नरसंहार की तमाम त्रासदियों को बीबीसी ने नजरअंदाज किया है।

बीबीसी मात्र सस्ती लोकप्रियता हासिल करने के कारण ही गुजरात दंगों को मोदी से जोड़ कर देखता है जबकि भारत के न्यायालयों के द्वारा गहराई से की गई जांचों में वे निर्दोष साबित किये जा चुके है। मात्र भारत के कुछ विरोधी राजनीतिक दल अपनी राजनीति चमकाने के लिए ही विदेशी मीड़िया को उकसाते रहते है। इसी कारण से वे ऐसे हास्यास्पद निष्कर्ष पर पहुंचते है कि भारत से ज्यादा खुशी पाकिस्तान में देखी जाती है। बीबीसी की यह हरकत बहुत ही निन्दनीय है।

अब भारत को भी ब्रिटिश इंड़िया पर जबाबी ड़ाक्यूमेंट्री बनानी चाहिए ताकि विश्व में यह पता लग सके कि ब्रिटिश शासन में भारतीयों पर क्या–क्या अत्याचार हुए? पश्चिमी देश कहते है कि भारत को इससे घबराना नहीं चाहिए। इन पश्चिमी देशों में भी रुसी चैनल रशिया टूड़े के प्रसारण पर से प्रतिबंध हटा देना चाहिए। बीबीसी यह दिखाती है कि वह अल्पसंख्यकों के साथ होने वाले दुर्व्यवहार को लेकर चिंतित है। तो ऐसी हालत में बीबीसी को भारत के पड़ोसी देशों में वहां के गैर मुस्लिम अल्पसंख्यकों पर ड़ाक्यमेंट्री जरुर बनानी चाहिए। बीबीसी को अपना वामपंथी मुखौटा हटाना चाहिए तथा मनुष्य व मानवता को सर्वोच्च स्थान देना चाहिए। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की भारत में छवि एक प्रखर राष्ट्रवादी की बनती जा रही है जिनके लिए राष्ट्र भारत ही प्रथम है उन पर कोई आरोप चिपक ही नहीं पा रहा है। ❑❑

डॉ. सूर्य प्रकाश अग्रवाल सनातन धर्म महाविद्यालय मुजफ्फरनगर 251001 (उ.प्र.), के वाणिज्य संकाय के संकायाध्यक्ष व ऐसोसियेट प्रोफेसर के पद से व महाविद्यालय के प्राचार्य पद से अवकाश प्राप्त हैं तथा स्वतंत्र लेखक व टिप्पणीकार है।

'गिग' अर्थव्यवस्था की त्रासदी

हाल ही में 'बलिंकिट' नाम की एक ई–कॉमर्स कंपनी के डिलीवरी कामगारों ने एक दिन की हड़ताल की थी, जिसको मीडिया ने भी खासा महत्व दिया था। मामला यह था कि 'बलिंकिट' नाम की कंपनी जो उपभोक्ताओं को उनकी किराना आवश्यकताओं की आपूर्ति 10 मिनट से आधे घंटे के बीच में करने का दावा करती है, ने अपने डिलीवरी एजेंटों का मेहनताना घटाकर आधा कर दिया था। गौरतलब है कि इस बदलाव से पहले कंपनी प्रत्येक डिलीवरी पर डिलीवरी एजेंट को 25 रूपए दिया करती थी। आज से लगभग एक साल पहले तक डिलीवरी एजेंटों को 50 रूपए प्रति डिलीवरी दिया जाता था। डिलीवरी श्रमिकों का कहना है कि इस दौरान ईंधन की लागत में बेतहाशा वृद्धि हुई है, लेकिन उनका मेहनताना एक चौथाई रह गया है।

वास्तविकता यह है कि आज बड़े शहरों में युवा किसी अच्छे रोजगार के अभाव में डिलीवरी एजेंट के रूप में काम करने के लिए बाध्य हो रहे हैं। शुरूआती दौर में ये श्रमिक भी अच्छा खासा कमा लेते थे, लेकिन मेहनताना कम होने के कारण अब उनकी आर्थिक हालत बहुत दयनीय हो गई है। वास्तविकता यह है कि वैकल्पिक रोजगार के अभाव में युवाओं के लिए डिलीवरी एजेंट के नाते काम करना उनकी मजबूरी हो गई है।

उधर एप आधारित टैक्सी सेवा प्रदान करने वाली 'ओला' और 'ऊबर' सरीखी कंपनियों ने भी टैक्सी ड्राइवरों से अत्यंत शोषणकारी तरीके से कमीशन वसूलना शुरू कर दिया है। इसके चलते 'ओला' और 'ऊबर' के ड्राइवर भी कई बार हड़ताल जैसे तरीके अपना चुके हैं। लेकिन 'ओला' और 'ऊबर' की शोषणकारी कमीशन नीति बदस्तूर जारी है। बिलिंकिट के डिलीवरी एजेंटों की हड़ताल के बावजूद कोई समाधान नहीं निकला है।

'ओला', 'ऊबर' के ड्राइवर हो, 'बलिंकिट', 'जोमेटो', 'स्वीगी' इत्यादि के डिलीवरी ऐजेंट हो अथवा एप आधारित किसी अन्य सेवा प्रदाता पर पंजीकृत अन्य प्रकार के कामगार हों, जिनका रोजगार इन एप कंपनियों के रहमोकरम पर चलता है या जिनकी रोजी–रोटी इन एप से प्राप्त संदेशों के आधार पर माल की डिलीवरी अथवा सेवा के ऑर्डर पर निर्भर करती है, आज इन कंपनियों के द्वारा किए जा रहे शोषण से पीड़ित हैं। ऐसे सभी कामगार जो

इस युग में नीति निर्माताओं से अपेक्षा है कि वे सभ्य समाज के निर्माण की ओर आगे बढ़ें, जंगल राज की तरफ नहीं। भारत सरकार से अपेक्षा है कि वे इन ऑनलाइन प्लेटफॉर्मों के श्रमिकों यानि 'गिग' श्रमिकों की सामाजिक सुरक्षा हेतु योजनाएं बनाए।
– स्वदेशी संवाद

इस प्रकार से अस्थाई रूप से काम कर रहे हैं, उन्हें आजकल की भाषा में 'गिग वर्कर' कहा जाता है।

आजकल 'गिग' शब्द अत्यधिक प्रचलन में है। आज से दो–तीन दशक पहले तक गिग शब्द का बहुत कम उपयोग होता था। 'गिग' शब्द का अर्थ और 'गिग' अर्थव्यवस्था और 'गिग वर्कर' आदि शब्दों को समझना और समाज पर इसके प्रभावों को जानना जरूरी हो गया है।

आज से दो–तीन दशक पहले कामगारों के दो प्रकार होते थे। एक, वेतनभोगी कर्मचारी और दूसरे, आकस्मिक श्रमिक। वेतनभोगी श्रमिक सामान्यतः स्थायी रूप से एक निश्चित वेतन और अन्य सुविधाओं के साथ नियुक्त होते हैं। इन श्रमिकों को हटाने के लिए एक निश्चित प्रक्रिया अपनाया जाना जरूरी था। दूसरी तरफ आकस्मिक श्रमिक यानि 'केजुअल लेबर' से अभिप्राय दिहाड़ीदार मजदूरों से होता है। इन मजदूरों को प्रत्येक दिन के हिसाब से मजदूरी मिलती है और उन्हें प्रतिदिन रोजगार की तलाश में जाना होता है।

संगठित क्षेत्र में सामान्यतः श्रमिकों की नियुक्ति स्थायी आधार पर होती है और उनके रोजगार की काफी हद तक सुरक्षा भी होती है। असंगठित क्षेत्र जैसे कृषि, कंस्ट्रक्शन और कई बार मैन्युफैक्चरिंग में दिहाड़ीदार मजदरों का चलन देखने को मिलता है । सामान्यतः शिक्षित एवं प्रशिक्षित कामगार वेतनभोगी होते हैं और दिहाड़ीदार मजदूरों में अधिकांश अशिक्षित एवं अप्रशिक्षित मजदूर होते हैं।

आज के युग में इन दोनों वर्गों से इतर एक नए प्रकार के श्रमिक वर्ग 'गिग वर्कर' का निर्माण हुआ है। नई टेक्नोलॉजी के आधार पर ऑनलाईन प्लेटफार्म, क्लाउड वर्किंग, फ्रीलांस वर्कर, ई–कॉमर्स, सप्लाई चेन, इत्यादि के रूप में यह नई श्रेणी उभरी है। यानि कहा जा सकता है कि नई टेक्नोलॉजी और नए बिजनेस मॉडल कहा जाता है, इस नई श्रमिक श्रेणी के जनक हैं।

तेज रफ्तार की इस दुनिया में हर कोई अपने आस्तित्व के लिए संघर्ष कर रहा है। आज की अराजक परिस्थितियों में श्रमिकों के आस्तित्व पर एक नया संकट आ गया है। तथाकथित रूप से ये श्रमिक काम तो कर रहे हैं और काम देने वाले एप भी सामने दिखाई देते हैं, लेकिन सरकारी परिभाषाओं में इन्हें श्रमिक यानि 'वर्कर' ही नहीं माना जाता बल्कि उन्हें 'फ्रीलांसर' कहा जाता है। ये वर्कर श्रमिकों के लिए निर्धारित न्यूनतम मजदूरी, काम के घंटे, ओवर टाईम और छुट्टी जैसे न्यूनतम लाभों से भी वंचित हैं।

कुछ लोग यह तर्क देने की कोशिश करते हैं कि इस 'गिग' अर्थव्यवस्था ने रोजगार के नए अवसर निर्माण किए हैं। अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन (आईएलओ) के द्वारा भी एप्स और ई–कॉमर्स प्लेटफार्मों के माध्यम से डिलीवरी श्रमिकों एवं ड्राइवरों इत्यादि के रूप में श्रमिकों की श्रेणी की व्याख्या की गई है। हालांकि पिछले कुछ समय से बेहतर कार्य–दशाओं और मेहनताने के लिए इन 'गिग' वर्करों द्वारा आंदोलन भी हुए हैं, लेकिन इनकी हालत में कोई सुधार होता दिखाई नहीं देता। 2017 के 'ई एंड वाई' के अध्ययन के अनुसार दुनिया के 24 प्रतिशत 'गिग' वर्कर भारत में हैं। भारतीय संसद द्वारा हाल ही में सामाजिक सुरक्षा के नए कोड के रूप में पारित श्रम कानून में पहली बार इन श्रमिकों को श्रम कानूनों के दायरे में लाने का प्रयास हुआ है।

दुनियाभर में इस प्रकार के 'गिग' वर्करों की सामाजिक सुरक्षा में सबसे बड़ी बाधा यह आ रही है कि इन वर्करों को चिन्हित कैसे किया जाए। अमरीका और यूरोप में इन कामगारों के लिए पूर्व निर्धारित और पारदर्शी कार्यदशाओं के संबंध में कुछ काम हुआ है। लेकिन विषय केवल इन एप से काम प्राप्त करने वाले श्रमिकों का ही नहीं है। आज के युग में कांट्रक्ट लेबर, आउटसोर्स लेबर, अस्थाई लेबर, निश्चित अवधि के कर्मचारी इत्यादि सभी कमोवेश शोषण एवं प्रतिकूल कार्यदशाओं के संकट से जूझ रहे हैं। आज जरूरत इस बात की है कि एक राष्ट्रीय रोजगार नीति बने, जिसमें आज के समय में उभरती प्रौद्योगिकियों, नए बिजनेस मॉडलों और नए–नए प्रकार से श्रमिकों के शोषण के सभी रास्ते बंद हों और हर कामगार चाहे वो स्थाई हो अथवा अस्थाई या गिग वर्कर, सभी एक सम्मानजनक जीवन व्यतीत कर सकें।

श्रमिकों को विस्थापित करने वाली नई–नई प्रौद्योगिकियों के कारण पुराने रोजगार नष्ट हो रहे है और अत्यंत सीमित नए रोजगारों का सृजन हो रहा है। काम के अभाव में जीने के लिए श्रमिक सभी प्रकार के शोषणों के बावजूद काम करने के लिए मजबूर हैं। लेकिन एक सभ्य समाज में श्रमिकों की इस दुर्गति को किसी भी प्रकार से स्वीकार नहीं किया जा सकता।

ऐसे सभी 'गिग', अस्थाई, कांट्रक्ट वर्करों को भलीभांति परिभाषित और चिन्हित करने का काम करते हुए उनके लिए न्यूनतम मजदूरी, अधिकतम काम के घंटे और विभिन्न प्रकार की सामाजिक सुरक्षा को सुनिश्चित करना होगा। ऐसा नहीं होने पर यह व्यवस्था जंगल राज से ज्यादा कुछ नहीं कहलाएगी, जिसका नियम है केवल योग्यतम को ही जीने का अधिकार है यानि 'सरवायवल ऑफ दि फिटेस्ट'। जाहिर है कि इस युग में नीति निर्माताओं से अपेक्षा है कि वे सभ्य समाज के निर्माण की ओर आगे बढ़ें, जंगल राज की तरफ नहीं। भारत सरकार से अपेक्षा है कि वे इन ऑनलाइन प्लेटफॉर्मों के श्रमिकों यानि 'गिग' श्रमिकों की सामाजिक सुरक्षा हेतु योजनाएं बनाए। ❑❑

टमाटर के बहाने बाजार का न्याय

अक्सर हमें टमाटर उत्पादक किसानों के चेहरे पर मुस्कराहट नहीं दिखाई देती। मात्र एक महीने पहले महाराष्ट्र के किसान अपने टमाटर सड़कों पर फेंक रहे थे, क्योंकि खबरों के मुताबिक टमाटर के थोक मूल्य में दो रुपये प्रति किलो की गिरावट आ गई थी। लेकिन अब कहानी बदल गई है। कई शहरों में टमाटर के खुदरा मूल्य सौ रुपये प्रति किलोग्राम को पार कर गए हैं और मजे की बात यह है कि किसानों को भी अपेक्षाकृत ज्यादा दाम मिल रहे हैं।

हिमाचल प्रदेश से खबर है कि टमाटर उत्पादक किसानों को 102 रुपये प्रति किलोग्राम की दर से अधिकतम कीमत मिल रही है, जो सेब की कीमत से भी ज्यादा है। यहां तक कि पंजाब में भी किसानों को 80 से 100 रुपये प्रति किलोग्राम के मिल रहे हैं, जबकि शॉपिंग मॉल में उपभोक्ता के लिए कीमत 97 से 137 रुपये प्रति किलोग्राम है। इसे दूसरे शब्दों में कहें, तो मुनाफे में व्यापारियों के हिस्से में काफी कमी आई है, जिसके चलते किसानों को मोटे तौर पर अंतिम उपभोक्ता मूल्य का 70 से 80 फीसदी हिस्सा मिल रहा है। मैं चाहूंगा कि तमाम सब्जियों और फलों के मामलें में यह प्रवृत्ति देखने को मिले।

भारतीय रसोई के एक महत्त्वपूर्ण मसाले– जीरे का थोक मूल्य भी बढ़ गया है। बारिश के कारण उत्पादन में भारी गिरावट और निर्यात के लिए मांग बढ़ने से जीरे का थोक मूल्य बढ़कर 55,750 रुपये प्रति क्विंटल तक पहुंच गया। इसके अलावा, जलवायु संबंधी अनियमितताओं के कारण इस सीजन में हिमाचल प्रदेश में ताजा सेब की फसल में 50 फीसदी की गिरावट आने की आशंका है। ऐसे में लगता है कि जब बाजार में नई फसल आएगी, तो उसकी खुदरा कीमतें अपेक्षाकृत ज्यादा होंगी। इसका मतलब है कि किसानों को उम्मीद से बेहतर कीमत मिलेगी। इसका एक संदेश बिल्कुल साफ है कि जब तक किसान अतिरिक्त फसल उत्पादित करने के जुनून से बाहर नहीं निकलेंगे, बाजार उनके साथ न्याय नहीं करेगा।

सिर्फ कर्मचारियों के लिए ही क्यों, किसानों के लिए मूल्य निर्धारण मानदंड तय करने की खातिर भी एक विशेषज्ञ समिति गठित करने की आवश्यकता है।

– देविंदर शर्मा

आमतौर पर सब्जियों और फलों के उपभोक्ता मूल्य में बढ़ोतरी का लाभ किसानों को नहीं दिया जाता है। मांग और आपूर्ति का समीकरण हमेशा काम नहीं करता है। ज्यादातर देखा गया है कि खुदरा व्यापार की कीमतों में हेर–फेर से उपभोक्ता कीमतों में अचानक बहुत तेज वृद्धि होती है। उपभोक्ताओं को जहां अधिक कीमत चुकाने के लिए मजबूर किया जाता है, वहीं किसानों को बढ़े हुए मूल्य का लाभ नहीं दिया जाता है। अब शिमला मिर्च का ही उदाहरण ले लीजिए, कुछ ही हफ्ते पहले पंजाब के किस्तन शिमला मिर्च को सड़कों पर फेंक रहे थे, क्योंकि व्यापारी उन्हें एक रुपये प्रति किलोग्राम की दर से भी कीमत नहीं देना चाह रहे थे। जबकि फेरी वाले शहरी उपभोक्ताओं से प्रति किलोग्राम शिमला मिर्च की कीमत 30 रुपये तक वसूल रहे थे।

इसका मतलब है कि बाजार में बिचौलियों का कमीशन 2,900 फीसदी होगा, जो एक तरह से शोषण है किसान प्याज को दो से तीन रुपये प्रति किलोग्राम की दर से बेच रहे थे, लेकिन खुदरा बाजार में इसकी कीमत 20 रुपये प्रति किलोग्राम थी, जो बताता है कि व्यापारियों को 900 फीसदी मुनाफा मिल रहा था।

हम इसे बाजार की चतुराई कहकर खारिज कर सकते हैं, लेकिन वास्तव में यह किसानों के लिए जीवन–मरण का प्रश्न है जरा उस झटके की कल्पना कीजिए, जो किसानों की आजीविका पर हमले करता है। जब किसान उत्पादन लागत भी नहीं मिलने पर अपनी मेहनत से उपजाई फसल को नष्ट करने के लिए मजबूर होते हैं। कुछ महीने पहले छत्तीसगढ़ से एक खबर आई थी, जिसमें बताया गया था कि कैसे महासमुंद के एक किसान को पूरी तरह से नुकसान उठाना पड़ा था, जब उसे रायपुर मंडी में 1,475 किलोग्राम बैंगन बेचने पर परिवहन एवं अन्य बच्चों को पूरा करने के लिए अपनी जेब से 121 रुपये का भुगतान करना पड़ा।

सिर्फ भारत ही नहीं, अमेरिका और ब्रिटेन में भी किसानों को नुकसान उठाना पड़ता है। अमेरिका में जहां अंतिम उपभोक्ता मूल्य में से किसानों की हिस्सेदारी तेजी से घटी है, वहीं ब्रिटेन में एक अध्ययन से पता चलता है कि कृषि व्यवसाय करने वाली कंपनियां दैनिक उपयोग में आने वाले आधा दर्जन उत्पादों की बिक्री से होने वाले मुनाफे का मुश्किल से एक फीसदी हिस्सा ही किसानों को देती है।

सिर्फ भारत ही नहीं, अमेरिका और ब्रिटेन में भी किसानों को नुकसान उठाना पड़ता है। अमेरिका में जहां अंतिम उपभोक्ता मूल्य में से किसानों की हिस्सेदारी तेजी से घटी है, वहीं ब्रिटेन में एक अध्ययन से पता चलता है कि कृषि व्यवसाय करने वाली कंपनियां दैनिक उपयोग में आने वाले आधा दर्जन उत्पादों की बिक्री से होने वाले मुनाफे का मुश्किल से एक फीसदी हिस्सा ही किसानों को देती है।

इस तरह की विसंगतियां बाजार संचलन के तरीके में खामियों का परिणाम है। हालांकि हर तरह के आर्थिक सुधार किए गए हैं, लेकिन व्यापार के क्षेत्र में बहुत सुधार नहीं हुए हैं। यह अनिवार्य है, क्योंकि कृषि आपूर्ति श्रृंखला बेहद जटिल है, जिसमें अन्य भागीदार तो मुनाफा कमा ले जाते हैं, लेकिन किसान ही उससे वंचित रह जाते हैं उपभोक्ताओं को समझना चाहिए कि सिर्फ किसान ही नहीं, बल्कि वे भी व्यापारियों द्वारा ठगे जा रहे हैं। मुक्त बाजारों के भरोसे छोड़ने से दुनिया में कहीं भी किसानों को उच्च आय नहीं मिल पाई है। अगर बाजार किसानों को लाभ पहुंचाता, तो कोई वजह नहीं थी कि अमेरिका को हर साल प्रति किसान 79 लाख रुपये की घरेलू सहयता प्रदान करनी पड़ती।

जाहिर है, कृषि व्यापार (जिसमें थोक एवं खुदरा बाजार, दोनों शामिल हैं) में तत्काल सुधार की आवश्यकता है और यह सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि किसानों की अंतिम उपभोक्ता मूल्य का न्यूनतम 50 फीसदी हिस्सा मिले। यदि टमाटर का खुदरा मूल्य 100 रुपये प्रति किलोग्राम है, तो किसानों को कम से कम 50 रुपये प्रति किलोग्राम कीमत मिले और बाजार यदि इस्स्से भी ज्यादा कीमत किसानों को दे सकता है, तो वह स्वागत योग्य है। जिस तरह अमूल कोऑपरेटिव यह सुनिश्चित करता है कि डेयरी किसानों को अंतिम उपभोक्ता मूल्य का कम से कम 80 फीसदी मिले, उसी तरह फलों एवं सब्जियों के व्यापार में भी करने की जरूरत है।

जैसा कि खबरों में बताया गया है, यदि सरकार कर्मचारियों के लिए पेंशन फंड को बाजार से जोड़ने की योजना बना रही है, ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि उन्हें अंतिम वेतन का कम से कम 40 फीसदी पेंशन मिल सके, तो मुझे कोई कारण नहीं दिखता कि आपूर्ति खला संतुलन को इसी तरह समायोजित नहीं किया जा सकता, ताकि किसानों को खुदरा मूल्य का कम से कम 50 फीसदी मिल सके। सिर्फ कर्मचारियों के लिए ही क्यों, किसानों के लिए मूल्य निर्धारण मानदंड तय करने की खातिर भी एक विशेषज्ञ समिति गठित करने की आवश्यकता है। ❑❑

आत्मनिर्भरता और विकास का लक्ष्य

घरेलू उद्योगों की मजबूती से दूर होगी बेरोजगारी

'आत्मनिर्भर–भारत' की दिशा में देश की यात्रा, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार समझौतों के निहितार्थ, नवाचार, उद्यमिता और रोजगार के बीच संतुलन जैसे अनेक ज्वलंत आर्थिक मुद्दों पर प्रख्यात सांख्यिकीय संगठन इंडिया स्टेट के लिए अर्थशास्त्री डॉ. अश्वनी महाजन से वरिष्ठ पत्रकार महिमा शर्मा ने लंबी बातचीत की है। डॉ. महाजन ने मौद्रिक चुनौतियों, भारत की अर्थव्यवस्था पर रूपए के मूल्यह्रास के प्रभावों तथा आत्मनिर्भरता के रास्ते तत्काल रोजगार सृजन पर बेबाकी से अपनी राय प्रकट की है। स्वदेशी पत्रिका के पाठकों के लिए प्रस्तुत है साक्षात्कार का संपादित अंश...

वैश्वीकरण के मौजूदा दौर में भारत अपने घरेलू उद्योगों को मजबूत करते हुए आत्मनिर्भरता को कैसे बढ़ावा दे सकता है?

नई आर्थिक नीति के बाद दुनिया के विभिन्न हिस्सों विशेषकर चीन से बढ़ते आयात के कारण हमारा औद्योगिक आधार कमजोर होने लगा। हमारे उद्योगों की गिरावट में सबसे अधिक योगदान चीनी आयात का रहा है। चीन से आयात बढ़ने के कारण हमारे कपड़ा, रसायन, इलेक्ट्रॉनिक्स, मशीनरी उपकरण, बिजली, दूरसंचार उपकरण, कागज और कागज के उत्पाद, बुनियादी धातु, परिष्कृत उत्पाद से संबंधित उद्योग सबसे अधिक प्रभावित हुए हैं। कई अन्य मामलों में बेतहाशा आयात के चलते भारत में चल रही फैक्ट्रियों को बंद तक करना पड़ा है। भारतीय उद्योगों के विनाश की यह प्रक्रिया 2001 में चीन के डब्ल्यूटीओ का सदस्य बनने के बाद और तेज हो गई। यही कारण है कि हमारे सकल घरेलू उत्पाद में विनिर्माण की हिस्सेदारी जो वर्ष 1995–96 में 21. 26 प्रतिशत थी, में गिरावट आई और 2018–19 में यह नीचे गिर कर 16.35 प्रतिशत पर आ गई।

भारी तादाद में युवा श्रम शक्ति वाले भारत जैसे देश में विनिर्माण क्षेत्र रोजगार और आजीविका के व्यापक अवसर प्रदान कर सकता है लेकिन दुर्भाग्य से न केवल हमने तीन महत्वपूर्ण दशक को दिए, जिसके दौरान हम अपने विनिर्माण को बढ़ावा दे सकते थे, बल्कि हमारे नीति निर्माता इस नुकसान के प्रति उदासीन और असंवेदनशील भी बने रहे। भारतीय उद्योगों को बचाने के लिए आगे आने की बजाय उन्होंने विनिर्मित उत्पादों के आयात के पक्ष में तर्क देते हुए कहा कि सस्ते आयात से हमारे लोगों के लिए कई सामान खरीदना संभव हो जाएगा और इससे उनकी जीवनशैली में भी सुधार होगा।

उल्लेखनीय है कि 2004 से पहले सरकार आयातित विनिर्मित और कृषि वस्तुओं पर भारी शुल्क लगाती थी। वर्ष 1990 में डब्ल्यूटीओ लागू होने से पहले आयात पर औसत भारित टैरिफ 56.36प्रतिशत था। 1992 में जब डब्ल्यूटीओ वार्ता चल रही थी तब इसे घटाकर 27.01 प्रतिशत कर दिया गया था। साल 1996 आते–आते इसे घटाकर 23.72 प्रतिशत कर दिया गया। मालूम हो कि डब्ल्यूटीओ समझौते वर्ष 1995 में लागू हुए थे वर्ष 2004 में औषध भारित टैरिफ 22. 96 प्रतिशत था, 2004 के बाद से सरकारों ने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा और टैरिफ में लगातार गिरावट जारी रही। वर्ष 2005 में औसत भारित टैरिफ 13.9 प्रतिशत था जो कि 2007 में कम होकर एक 11.99 प्रतिशत हो गया और 2008 में और घटकर यह 5.99 प्रतिशत पर आ गया। सबसे कम औसत भारित प्रेरित 2018 में था जब यह घटकर 4.88 प्रतिशत पर आ गया था। वर्ष 2018 के बाद से सरकार ने आयात की कुछ चयनित वस्तुओं पर टैरिफ बढ़ाने का प्रयास किया जिसमें इलेक्ट्रॉनिक दूरसंचार मोबाइल फोन कपड़ा परिधान और गैर आवश्यक वस्तुएं शामिल थी। इन सारे प्रयासों के बावजूद वर्ष 2020 में औसत भारित टैरिफ 6.19 प्रतिशत ही रहा।

कोविड–19 महामारी के दौरान शिद्दत के साथ यह महसूस किया गया कि देश आयातित वस्तुओं पर निर्भर नहीं रह सकता। देश को कुछ हद तक आत्मनिर्भरता हासिल करने की जरूरत है। इसी सोच के तहत 'आत्मनिर्भर भारत' का लोकप्रिय कार्यक्रम शुरू हुआ है। सरकार ने उन क्षेत्रों वस्तुओं की एक सूची तैयार की है जो चीन से असामान आयात से बुरी तरह प्रभावित हुए हैं। चीन द्वारा सामानों की भारी मात्रा में डंपिंग, चीन के अधिकारियों द्वारा व्यापार नियमों का उल्लंघन या ऐसे किसी अन्य चालबाजियों से

ठीक–ठाक के पड़े भारतीय उद्योगों के पुनरुद्धार के लिए सरकार ने उत्पादन से जुड़ी प्रोत्साहन योजना की पेशकश की है।वर्तमान सरकार ऐसे उद्योगों के पुनरुद्धार के लिए प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से समर्थन दे रही है। सरकार के इन प्रयासों के बहुत उत्साहजनक परिणाम विनिर्माण के इन क्षेत्रों में देखने को मिल रहे हैं कई नई एपीआई विनिर्माण क्षमताएं बनाई जा रही है और देश एक बार फिर एपीआई के उत्पादन में आत्मनिर्भर बनने की ओर अग्रसर है यही स्थिति विनिर्माण के अन्य क्षेत्रों की भी है। लेकिन विडंबना पूर्ण है कि एक तरफ विभिन्न उत्पादों के लिए नई क्षमताएं बनाई जा रही है वहीं दूसरी तरफ चीन से आयात बेरोकटोक अब भी जारी है।

भारतीय रुपए की वर्तमान स्थिति और अर्थव्यवस्था पर इसके प्रभाव के बारे में आप का आकलन किया है रुपए में अंतरराष्ट्रीय व्यापार के निपटान की अनुमति देने संबंधी भारतीय रिजर्व बैंक के फैसले का असर क्या होगा?

पिछले कुछ समय से अमेरिकी डालर के मुकाबले भारतीय रुपया कमजोर हो रहा है और फरवरी 2022 में रुपया 74.5 रुपए प्रति अमेरिकी डालर से घटकर अब 82 रुपए प्रति अमेरिकी डालर पर आ गया है।

अतीत में रुपया न केवल अमेरिकी डालर के मुकाबले बल्कि यूरो, पाउंड, येन और युआन सहित कई महत्वपूर्ण मुद्राओं के मुकाबले कमजोर हो रहा था। उदाहरण के लिए वर्ष 1991 के बाद से पाउंड स्टर्लिंग के मुकाबले रूपए में 137प्रतिशत, यूरो के मुकाबले 489प्रतिशत और येन के मुकाबले 241प्रतिशत की गिरावट आई है, जबकि यूएसडी के मुकाबले मूल्य हास 252प्रतिशत रहा है। इसका मतलब यह है कि लंबी अवधि में रुपया सभी महत्वपूर्ण मुद्राओं के मुकाबले कमजोर हुआ है।

लेकिन हाल के दिनों में रुपए के अवमूल्यन के रुख में बदलाव आया है फरवरी 2022 से जून 2023 तक अमेरिकी डॉलर के मुकाबले रुपया 10.5 प्रतिशत कमजोर हुआ, लेकिन ब्रिटिश पाउंड के मुकाबले केवल 2.4 प्रतिशत और यूरो के मुकाबले 5.1 प्रतिशत की गिरावट आई जबकि जापानी येन के मुकाबले लगभग 9 प्रतिशत की वृद्धि हुई है। पूर्व में जुलाई 2022 से पहले के 5 महीनों में पाउंड स्टर्लिंग के मुकाबले 6.13 प्रतिशत, येन के मुकाबले 10.77 प्रतिशत और यूरो के मुकाबले 4.72 प्रतिशत की बढ़ोतरी हुई थी। चूंकि यूएसडी दुनिया भर की लगभग सभी प्रमुख मुद्राओं के मुकाबले मजबूत हुआ है, इसलिए रुपए की कमजोरी के बजाय विभिन्न मुद्राओं के मुकाबले अमेरिकी डालर की मजबूती के कारणों को समझना हमारे लिए अधिक फायदेमंद है।

भारतीय रुपए में व्यापार के निपटान की सुविधा के लिए भारतीय बैंकों ने यूके, न्यूजीलैंड, जर्मनी, मलेशिया, इजराइल, रूस और संयुक्त अरब अमीरात सहित 19 देशों के साथ विशेष वोस्ट्रो खाते खोले हैं। रूस की तरह ही इन 19 देशों में से कुछ देश भारत को भारी निर्यात करते हैं और उन्हें उनके निर्यात के लिए भारतीय रुपए में भुगतान किया जाएगा।

जुलाई 2022 में भारतीय रिजर्व बैंक ने एक परिपत्र के माध्यम से भारतीय रुपए में वस्तुओं और सेवाओं के आयात और निर्यात के लिए निपटान की अनुमति दी है।यह रूस और यूक्रेन युद्ध के कारण रूस और ईरान को भुगतान के लिए अमेरिकी डालर के उपयोग पर अमेरिकी प्रतिबंधों की पृष्ठभूमि में एक रणनीतिक निर्णय था। एक अन्य कारण भारतीय निर्यात को बढ़ावा देकर भारतीय रुपए की कमजोरी का समर्थन करना था जिसके परिणाम स्वरूप विदेशी व्यापार में वृद्धि हुई है। इस निर्णय के कारण दुनिया के कई देश जो भारत से आयात करने में रुचि रखते थे और अमेरिकी डालर की कमी के कारण ऐसा करने में सक्षम नहीं थे अब वे अपने आयात के लिए भारतीय रुपए में भुगतान कर सकते हैं। भारतीय रुपए में व्यापार के निपटान की सुविधा के लिए भारतीय बैंकों ने यूके, न्यूजीलैंड, जर्मनी, मलेशिया, इजराइल, रूस और संयुक्त अरब अमीरात सहित 19 देशों के साथ विशेष वोस्ट्रो खाते खोले हैं। रूस की तरह ही इन 19 देशों में से कुछ देश भारत को भारी निर्यात करते हैं और उन्हें उनके निर्यात के लिए भारतीय रुपए में भुगतान किया जाएगा। यह उचित रूप से माना जाता है कि ऐसे देश भारत से अधिक से अधिक उत्पाद आयात करने के लिए अपने भारतीय रुपए के भंडार का उपयोग करने की संभावना रखते हैं। यह भारत से निर्यात को पर्याप्त बढ़ावा दे सकता है जो उनके लिए आवश्यक भारत में उपलब्ध वस्तुओं या सेवाओं की गुणवत्ता और मात्रा के अधीन है। बढ़ते वैश्विक आर्थिक जोखिमों के बीच इस पूरी कवायद से बहुमूल्य विदेशी मुद्रा भंडार बचाने में मदद मिलेगी।

भारतीय रिजर्व बैंक के दिनांक 11 साथ 2022 के परिपत्र के अनुरूप भारतीय रुपए में अंतर्राष्ट्रीय व्यापार निपटान यानी भारतीय रुपए में आयात निर्यात के चालान भुगतान और निपटान की अनुमति देने के लिए विदेश व्यापार

नीति में आवश्यक परिवर्तन किए गए हैं। भारतीय रिजर्व बैंक के दिशा निर्देशों के अनुसार निर्यात लाभ प्रदान करने और भारतीय रुपए में निर्यात प्राप्तियों के लिए निर्यात दायित्वों की पूर्ति हेतु विदेश व्यापार नीति में भी बदलाव हुए हैं। यह परिवर्तन यह सुनिश्चित करेंगे कि निर्यातक निर्यात प्रोत्साहन के हकदार बने रहें, भले ही उनके निर्यात का भुगतान भारतीय रुपए में किया जाए। इस निर्णय से अंतरराष्ट्रीय व्यापार में अमेरिकी डालर की आवश्यकता कम हो जाएगी और भारतीय रुपए को मजबूत करने में मदद मिल सकती है। इससे मुद्रास्फीति से निपटने और रुपए को अंतरराष्ट्रीय मुद्रा बनाने सहित और भी कई लाभ होंगे।

2000 के नोटों के विमुद्रीकरण से भारतीय अर्थव्यवस्था पर क्या प्रभाव पड़ेगा कृपया लाभ और हानि दोनों बताएं?

पूर्व में 1000 और 500 के बड़े नोटों को बंद करने के नाम पर 2000 का नोट जारी करना नोटबंदी की मूल भावना के ही खिलाफ था। इसीलिए मार्च 2018 में 2000 के नोटों को वापस लेने की शुरुआत की गई थी गौरतलब है कि शुरुआत में चलन में आए 6.73 लाख करोड़ रुपए के 2000 के नोट मार्च 2023 तक घटकर सिर्फ 3.62 लाख करोड़ रुपए रह गए थे। हालांकि सरकार ने 2000 के नोट जारी किए थे लेकिन सरकार का इरादा धीरे–धीरे इन नोटों के प्रचलन को कम करना और अंततः इन्हें पूरी तरह से वापस लेना था रिजर्व बैंक का कहना है कि मार्च 2017 से पहले जारी किए गए कुल 2000 रूपये की नोटों में से 89 प्रतिशत नोट अपनी मियाद पूरी कर चुके हैं और भारतीय रिजर्व बैंक की स्वच्छ नोट नीति के तहत इन्हें वापस लिया ही जाना था। निष्कर्ष है कि 2000 रूपये के नोटों को वापस लेने को अचानक लिया गया फैसला नहीं कहा जा सकता। रिजर्व बैंक का कहना है कि आम जनता के पास 2000 रूपये के नोट बहुत कम है इसका मतलब यह भी है कि प्रचलन में 2000 रूपये के नोट ज्यादातर उन लोगों के पास है जिन्होंने अपना पैसा नगदी (या कहे काला धन) के रूप में रखा है।इसलिए रिजर्व बैंक का कहना है कि इस फैसले से बैंकों की जमा राशि में भारी बढ़ोतरी हो सकती है। इससे सरकार का राजस्व बढ़ेगा और अर्थव्यवस्था में और अधिक पारदर्शिता भी आएगी।

मुद्रास्फीति से निपटने, अधिक पारदर्शिता लाने, डिजिटलीकरण, अपराध, आतंकवाद, पत्थरबाजी और यहां तक कि नक्सलवाद को नियंत्रित करने, सरकारी राजस्व को बढ़ाने आदि के मामले में नोटबंदी भारत के लिए फायदेमंद रही है।

मुद्रास्फीति से निपटने, अधिक पारदर्शिता लाने, डिजिटलीकरण, अपराध, आतंकवाद, पत्थरबाजी और यहां तक कि नक्सलवाद को नियंत्रित करने, सरकारी राजस्व को बढ़ाने आदि के मामले में नोटबंदी भारत के लिए फायदेमंद रही है। 2000 रुपए के नोटधारक इन्हें अन्य मुद्राओं में बदल सकते हैं। बदलने वालों में से अधिकांश या तो उन्हें बैंक खातों में जमा करेंगे और करों का भुगतान करेंगे या कोई विशिष्ट खपत बढ़ा सकते हैं, इससे अर्थव्यवस्था को लाभ होगा। अर्थशास्त्रियों का मानना है कि इससे बैंक जमा में न्यूनतम एक लाख करोड रुपए की बढ़ोतरी हो सकती है।

बड़ी जनसंख्या प्रमुख चिंता का विषय बन गई है। वर्तमान आर्थिक परिदृश्य में भारत बेरोजगारी और रोजगार सृजन की चुनौतियों का समाधान कैसे कर सकता है?

सबसे पहले हमें यह समझने की आवश्यकता है कि वर्तमान में भारत में चिंता जनसंख्या के आकार को लेकर नहीं है बल्कि हमारे युवाओं की तैनाती की है। विशेष रूप से 15 से 30 वर्ष के आयु वर्ग के युवाओं की संख्या लगभग जनसंख्या का 30 प्रतिशत है। इस जनसंख्या को वरदान माना जाता है और इसे जनसांख्यिकीय लाभांश भी कहा जाता है।

वैश्वीकरण के प्रति नीति निर्माताओं के जुनून के कारण पिछले लगभग 30 सालों में भारत में विनिर्माण क्षेत्र में उल्लेखनीय गिरावट आई है। साथ ही यह मानसिकता भी विकसित हो गई है कि भारत कभी भी विनिर्माण क्षेत्र में दुनिया से प्रतिस्पर्धा नहीं कर सकता इसलिए हमें केवल सेवा क्षेत्र पर ध्यान केंद्रित करने की जरूरत है हम अपनी आवश्यकताओं के लिए विदेशों से वस्तुएं आयात कर सकते हैं। यह मानसिकता विकसित करने का भी प्रयास किया गया कि घरेलू उत्पादन बढ़ाने के साथ–साथ निर्यात बढ़ाने के लिए भी आयात आवश्यक है। व्यापार घाटा बढ़ने और इसके परिणामस्वरूप विदेशी मुद्रा की मांग बढ़ने तथा रुपए के अवमूल्यन के बावजूद हमारे नीति निर्माताओं की सोच में कोई बदलाव नहीं आया।लेकिन करो ना काल के दौरान जब अंतरराष्ट्रीय आपूर्ति श्रृंखला बाधित हो गई और हमें आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति के लिए चीन पर निर्भर रहना पड़ा (जो उस महामारी का मुख्य दोषी था), तब देश में 'आत्मनिर्भर भारत' और 'वोकल फार लोकल' की एक नई सोच विकसित हुई। महामारी के उस कठिन समय में

भारत ने न केवल आवश्यक दवाएं टीका पीपी किट वेंटिलेटर और अन्य चिकित्सा उपकरणों का निर्माण किया बल्कि विभिन्न क्षेत्रों में भारत को आत्मनिर्भर बनाने के लिए वाहन प्रयास शुरू कर दिए।

पिछले कुछ वर्षों में आयात की बड़ी आमद के कारण जो क्षेत्र प्रभावित हुए हैं जैसे एपीआई, इलेक्ट्रॉनिक्स, कपड़ा और परिधान, दूरसंचार, रसायन आदि के साथ–साथ भारत के लिए आवश्यक उद्योगों जैसे सेमीकंडक्टर सोलर पैनल इलेक्ट्रिक वाहन आदि के लिए प्रयास शुरू हो गए हैं। उत्पादन से जुड़े प्रोत्साहन पीएलआई एंटी डंपिंग शुल्क लगाने तेरी बढ़ाने आदि के जरिए उद्योगों को पुनर्जीवित करने का काम शुरू हुआ है। सरकार अगले कुछ वर्षों में इन सभी पीएलआई पर लगभग 3 लाख करोड रुपए खर्च करने की योजना बना रही है प्रधानमंत्री द्वारा आत्मनिर्भर भारत योजना का कार्यान्वयन और वोकल फार लोकल का नारा वास्तव में इन क्षेत्रों में नई ऊर्जा का संचार कर रहा है।इन ऐतिहासिक प्रयासों को सफल बनाने के लिए कोई कसर नहीं छोड़ी जानी चाहिए सरकार को उद्यमियों और युवाओं तक ले जाने के लिए समाज के प्रयासों की जरूरत होगी देश में लगभग 700 औद्योगिक समूह हैं जिनमें से कई आयात के हमले और गैर अनुकूल व्यवसायिक माहौल के कारण विलुप्त होने के खतरे का सामना कर रहे हैं। कुछ राज्यों में एक जिला और एक उत्पाद योजना भी कई तरह के संकटों का सामना कर रही है ऐसे उद्योगों को पुनर्जीवित करने में बड़ी मदद मिल सकती है।

अपना सतत आर्थिक विकास सुनिश्चित करते हुए भारत मुद्रास्फीति के दबाव को प्रभावी ढंग से कैसे सुव्यवस्थित कर सकता है?

यद्यपि मुद्रास्फीति आम आदमी और व्यवसायियों को सीधे तौर पर प्रभावित कर रही है फिर भी मुद्रास्फीति की दर दुनिया की अन्य प्रमुख अर्थव्यवस्थाओं की तुलना में काफी कम है। मैन्युफैक्चरिंग हो या सर्विस सेक्टर सभी में तेजी से विकास के संकेत हैं जीएसटी की प्राप्ति यों के आंकड़े इसकी पुष्टि करते हैं डॉलर के मुकाबले रुपया थोड़ा कमजोर हुआ है लेकिन यह पहले जैसा नहीं है क्योंकि जब भी भारतीय मुद्रा कमजोर हो रही थी वह दुनिया की सभी प्रमुख मुद्राओं के मुकाबले कमजोर हो रही थी। लेकिन पिछले 5 महीनों में पाउंड यूरो और इनके मुकाबले रुपया मजबूत हुआ है।रुपए सहित अन्य प्रमुख मुद्राओं के मुकाबले डालर की मजबूती अमेरिका में ब्याज दरों में बढ़ोतरी और वैश्विक उथल–पुथल के कारण है इसीलिए यह माना जा रहा है कि डॉलर की मजबूती अल्पकालिक होगी। भारत के नीति निर्माताओं की मुख्य चिंता महंगाई है भारत में मुद्रास्फीति बहुत लंबे समय तक 3.00 से 4 प्रतिशत के बीच बहुत ही निचले स्तर पर बनी रही, लेकिन हाल ही में गिरावट से पहले कुछ समय के लिए यह 7प्रतिशत के शिखर पर पहुंच गई थी। ऊंची महंगाई के कारण रिजर्व बैंक को नीतिगत ब्याज दरें बढ़ानी पड़ी जिसका असर विकास पर भी पड़ा। मुद्रास्फीति की उच्च दर की स्थिति में सरकार को मुद्रास्फीति पर अंकुश लगाने के लिए ठोस प्रयास करने होंगे महंगाई से निपटने के लिए कई प्रयास किए गए हैं जिनमें रूस और ईरान से सस्ते दामों पर कच्चा तेल खरीदना देश में कृषि उत्पादन बढ़ाना और सरकार द्वारा पेट्रोल और डीजल पर टैक्स में कमी करना शामिल है इन सभी प्रयासों के कारण भारत में मुद्रास्फीति की दर अमेरिका और ब्रिटेन की तुलना में काफी कम है।

विश्व स्तर पर देश खाद्य मुद्रास्फीति धान की बढ़ती कीमतों और आवश्यक कच्चे माल की बढ़ती कीमतों का सामना कर रहे हैं कुछ हद तक भारत भी से प्रभावित हो रहा है लेकिन कर राजस्व बढ़ाकर और परिणाम स्वरूप राजकोषीय घाटे को नियंत्रित करके मुद्रास्फीति को नियंत्रित करने के प्रयास जारी है इसमें कोई संदेह नहीं है कि यदि भारत मुद्रास्फीति को नियंत्रित करने में सक्षम रहता है तो हम आत्मनिर्भर भारत के प्रयासों के बल पर देश के विभिन्न क्षेत्रों में विनिर्माण को बढ़ावा देकर अपनी जीडीपी और रोजगार दोनों को बढ़ाने में कामयाब होंगे।

नौकरियों के लिए न्यूनतम जोखिम सुनिश्चित करते हुए एआई के माध्यम से भारत में नवाचार और उद्यमिता को बढ़ावा देने के लिए सरकार को क्या भूमिका निभानी चाहिए?

आज भारत के सामने चुनौती न केवल पहली दूसरी और तीसरी औद्योगिक क्रांति में अपने संतोषजनक प्रदर्शन की भरपाई करने की है बल्कि चौथी औद्योगिक क्रांति में सक्रिय रूप से भाग लेने की भी है। यह सच है कि रोबोटिक्स कृत्रिम बुद्धिमता ड्रोन आदि के कारण रोजगार सृजन में कुछ कमी आ सकती है लेकिन इसकी भरपाई दुनिया में इन तकनीकों में अग्रणी बनकर इसके माध्यम से रोजगार पैदा करके की जा सकती है। हमें यह याद रखना चाहिए कि नई तकनीक के कारण लागत भी कम होती है। उदाहरण के लिए जो कंपनियां कृत्रिम बुद्धिमता रोबोट ड्रोन आदि का उपयोग करती हैं वह अपने लागत कम कर देती हैं लागत कम होने से वह उद्योग बाजार में अधिक प्रतिस्पर्धी हो जाते हैं लेकिन नई तकनीक के नाम पर रोजगार के अंदाज और नुकसान को भी उचित नहीं ठहराया जा सकता है। ऐसे में नीति निर्माताओं को प्रौद्योगिकी के चयन पर अत्यधिक संवेदनशीलता और गंभीरता से विचार करना होगा। ❑❑

https://www.indiastat.com/Socio-Economic-Voices/India-Pursuit-Self-Reliance-Economic-Growth-Strategies-Strengthen-Domestic-Industries-Address-Unemployment

अंतरराष्ट्रीय मुद्रा के रूप में भारतीय रुपया

वर्तमान में यह चर्चा गंभीर है कि विश्व की पाँचवी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था को अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा के रूप में स्थापित होना चाहिए। इसके लिए रिजर्व बैंक ने आवश्यक कदम उठाए है परंतु फिर भी कुछ आशंकाएं भी व्यक्त की जा रही हैं और उत्साहजनक रूप से प्रयास भी ही रहा है।

अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में रुपए में चालान–प्रक्रिया के लिये भारत की कोशिशों ने हालिया विदेश व्यापार नीति 2023 के साथ गति प्राप्त की है, जो भारतीय रुपए में व्यापार की चालान–प्रक्रिया, भुगतान और निपटान का प्रस्ताव करता है। इस कदम से अन्य लाभों के साथ–साथ लेन–देन की लागत कम होने, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को बढ़ावा मिलने और 'हेजिंग' व्यय के कम होने की उम्मीद है। रुपया वर्तमान में वैश्विक मुद्रा बाज़ार कारोबार में मात्र 2 प्रतिशत की हिस्सेदारी रखता है। यह फ्रेमवर्क रूस, सऊदी अरब, नाइजीरिया और संयुक्त अरब अमीरात जैसे व्यापार भागीदारों के लिये विशेष रूप से लाभप्रद सिद्ध हो सकता है। हालाँकि, इस नीति की प्रभावशीलता अंततः भारत के शुद्ध व्यापार घाटे/अधिशेष और कुल द्विपक्षीय व्यापार की तुलना में रुपए में व्यापार की सीमा जैसे कारकों पर निर्भर करती है।कुल मिलाकर, भारतीय रुपए के अंतर्राष्ट्रीयकरण को बढ़ावा देने के लिये सरकार, भारतीय रिज़र्व बैंक और अन्य हितधारकों की ओर से अंतर्राष्ट्रीय लेन–देन में भारतीय रुपए की मांग को बढ़ावा देने के लिये एक ठोस प्रयास की आवश्यकता होगी।

रुपए का अंतर्राष्ट्रीयकरण मुद्रा रूपांतरण की आवश्यकता को कम कर सकता है, जिससे अंतर्राष्ट्रीय व्यापार करने वाले व्यक्तियों के लिये लेन–देन की लागत कम हो सकती है। यह विदेशी निवेशकों के लिये भारत में व्यापार करने को और अधिक आकर्षक बना सकता है और वैश्विक बाज़ारों में भारत के निर्यात को अधिक प्रतिस्पर्द्धी बना सकता है। जब अंतर्राष्ट्रीय लेन–देन में रुपए का व्यापक रूप से उपयोग होगा तो यह मूल्य पारदर्शिता के वृहत स्तर की ओर ले जा सकता है। यह भारतीय कारोबारों को वैश्विक बाज़ार की

नीति निर्माताओं के लिए यही बेहतर होगा कि वे रुपये के अंतर्राष्ट्रीयकरण की प्रक्रिया को सतत रखें और वित्तीय बाजारों के विकास तथा अंतर राष्ट्रीय अपेक्षाओं के अनुरूप मजबूत वृहद आर्थिक बुनियाद तैयार करने पर ध्यान दिया जाए।

– विनोद जौहरी

स्थितियों को बेहतर ढंग से समझने और तदनुसार अपनी मूल्य निर्धारण रणनीतियों को समायोजित करने में सक्षम बना सकता है। रुपए का अंतर्राष्ट्रीयकरण अंतर्राष्ट्रीय लेन–देन के लिये त्वरित और अधिक कुशल निपटान समय की सुविधा प्रदान कर सकता है। यह सीमा–पार भुगतान से जुड़े समय और लागत को कम करके भारतीय कारोबारों को लाभान्वित कर सकता है।

अंतर्राष्ट्रीयकृत रुपया भारतीय व्यवसायों के लिये अपने वैश्विक समकक्षों के साथ लेन–देन करना सरल एवं सस्ता बनाकर अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को बढ़ावा दे सकता है। इससे देश के निर्यात और आर्थिक विकास में वृद्धि हो सकती है।रुपए की व्यापक स्वीकृति और अंतर्राष्ट्रीय लेन–देन में उपयोग की वृद्धि के साथ मुद्रा उतार–चढ़ाव के विरुद्ध हेजिंग की आवश्यकता कम हो सकती है। इससे व्यवसायों और निवेशकों के लिये लागत बचत हो सकती है।

अंतर्राष्ट्रीयकृत रुपया भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा विदेशी रिज़र्व रखने की लागत को कम कर सकता है। जब अंतर्राष्ट्रीय लेन–देन में रुपए का व्यापक प्रचलन और उसकी स्वीकृति होगी तो रिजर्व बैंक के लिये अपने कार्यकरण के संचालन हेतु अधिक विदेशी मुद्रा रखने की आवश्यकता नहीं होगी, जिससे लागत में कमी आएगी। भारत में अभी भी पूंजी नियंत्रण की स्थिति है जो भारतीय बाज़ारों में निवेश और व्यापार करने की विदेशियों की क्षमता को सीमित करता है। ये नियंत्रण भारतीय रुपए के लिये अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा के रूप में व्यापक रूप से उपयोग किये जाने को कठिन बनाते हैं। वैश्विक आरक्षित मुद्रा के रूप में उपयोग की जाने वाली किसी मुद्रा के लिये मुद्रा विनिमय दर स्थिरता एक महत्त्वपूर्ण आवश्यकता है। मुद्रा के अंतर्राष्ट्रीयकरण के लिये बड़े एवं तरल वित्तीय बाज़ारों का विकास एक पूर्व

सरकार को द्विपक्षीय मुद्रा विनिमय समझौतों पर हस्ताक्षर करके अपने व्यापारिक भागीदारों को अंतर्राष्ट्रीय लेन-देन में भारतीय रुपए का उपयोग करने के लिये प्रोत्साहित करना चाहिये। यह अपने पड़ोसी देशों के साथ एक भारतीय रुपया-आधारित व्यापारिक मंच बनाने की संभावना की भी तलाश कर सकती है।

शर्त है। भारतीय वित्तीय बाज़ार अभी भी विकास की प्रक्रिया में है और इसे वैश्विक वित्तीय बाज़ारों के साथ और अधिक एकीकृत करने की आवश्यकता है।

जब किसी मुद्रा के अंतर्राष्ट्रीयकरण की बात आती है तो मुद्रास्फीति की दर भी एक महत्त्वपूर्ण पहलू है। भारतीय रिज़र्व बैंक मुद्रास्फीति को नियंत्रण में रखने में सफल रहा है, लेकिन निम्न मुद्रास्फीति दर विदेशी निवेशकों के लिये मुद्रा को कम आकर्षक बना सकती है।

राजनीतिक अस्थिरता, युद्ध और प्रतिबंध जैसे भू–राजनीतिक कारक मुद्रा के अंतर्राष्ट्रीयकरण पर महत्त्वपूर्ण प्रभाव डाल सकते हैं। भारत को अन्य देशों के साथ स्थिर संबंध रखने और भू–राजनीतिक संघर्षों में लिप्त होने से बचने की आवश्यकता है, क्योंकि ये अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा के रूप में रुपये के उपयोग को प्रभावित कर सकते हैं।

सरकार को दूसरे देशों, विशेष रूप से नेपाल, भूटान और बांग्लादेश जैसे पड़ोसी देशों के साथ सीमा–पार व्यापार को अन्य मुद्राओं के बजाय भारतीय रुपए में किये जाने को प्रोत्साहित करना चाहिये। इससे इन देशों में भारतीय रुपए की मांग बढ़ेगी, जिससे इसके अंतर्राष्ट्रीयकरण को बढ़ावा मिलेगा। विदेशी निवेशकों को आकर्षित करने के लिये भारत अपने वित्तीय बाज़ारों, विशेष रूप से बॉण्ड बाज़ार के विकास को बढ़ावा दे सकता है। इससे भारतीय रुपए–मूल्यवर्ग के बॉण्ड की मांग बढ़ेगी और अंतर्राष्ट्रीय लेन–देन में इसके उपयोग को बढ़ावा मिलेगा।

सरकार को विदेशी निवेश को आकर्षित करने के लिये पूंजी खाता लेन–देन को और उदार बनाना चाहिये, जिससे अंतर्राष्ट्रीय लेन–देन में भारतीय रुपए की मांग बढ़ेगी। सरकार को द्विपक्षीय मुद्रा विनिमय समझौतों पर हस्ताक्षर करके अपने व्यापारिक भागीदारों को अंतर्राष्ट्रीय लेन–देन में भारतीय रुपए का उपयोग करने के लिये प्रोत्साहित करना चाहिये। यह अपने पड़ोसी देशों के साथ एक भारतीय रुपया–आधारित व्यापारिक मंच बनाने की संभावना की भी तलाश कर सकती है।

भारतीय रिजर्व बैंक की अंतर–विभागीय समिति ने अन्य देशों में रुपये में लेनदेन को लोकप्रिय बनाने तथा डॉलर पर निर्भरता कम करने के लिए आज कई कदम उठाने की सिफारिश की। श्री राधा श्याम राठो की अध्यक्षता वाली समिति ने रुपये को अंतरराष्ट्रीय मुद्रा के तौर पर प्रोत्साहित करने के लिए अल्पावधि, मध्यम अवधि और दीर्घावधि के उपाय सुझाए हैं। समिति ने कहा है कि रुपये के अंतरराष्ट्रीयकरण के लिए पूंजी खाता परिवर्तनीयता और पूंजी खाता परिवर्तनीयता के लिए रुपये का अंतरराष्ट्रीयकरण शर्त नहीं है। परिवर्तनीयता का मौजूदा स्तर रुपये को अंतरराष्ट्रीय मुद्रा बनाने के लिए काफी है। रिपोर्ट में कहा गया है कि 2022 में यूक्रेन पर रूस के हमले के बाद लगाए गए प्रतिबंधों के बाद कई देश सतर्क हो गए हैं और सोचने लगे हैं कि यदि पश्चिमी देश उन पर भी इसी

तरह के प्रतिबंध लगाते हैं तो उन्हें कितनी बड़ी कीमत चुकानी पड़ सकती है।रिपोर्ट के अनुसार इस तरह के वैश्विक घटनाक्रम और व्यापार तथा पूंजी प्रवाह के लिहाज से बाकी दुनिया के साथ भारतीय अर्थव्यवस्था का जुड़ाव बढ़ने से रुपये समेत कई मुद्राओं के अंतरराष्ट्रीय इस्तेमाल के लिए बुनियाद तैयार हो गई है।

भारत ने पूंजी खाता परिवर्तनीयता, वैश्विक मूल्य श्रृंखला के एकीकरण, गिफ्ट सिटी की स्थापना आदि के मामले में सराहनीय प्रगति की है। विदेशी व्यापार के चालान और निपटान के साथ–साथ पूंजी खाता लेनदेन में रुपये का ज्यादा उपयोग होने से रुपये की अंतरराष्ट्रीय मौजूदगी बढ़ती जाएगी।

रूस–यूक्रेन युद्ध के बाद से रिजर्व बैंक ने भी बैंकों को द्विपक्षीय व्यापार भारतीय मुद्रा में करने की इजाजत दे दी है। रिपोर्ट में कहा गया है कि श्रीलंका ने हाल ही में रुपये को विदेशी मुद्रा के रूप में जो मान्यता दी है, उससे रुपये का अंतरराष्ट्रीय दर्जा और भी पुख्ता होता है।

रिपोर्ट में मुद्रा के अंतरराष्ट्रीयकरण से आने वाली चुनौतियां भी बताई गई हैं क्योंकि शुरुआत में इसके विनिमय दर में उतार–चढ़ाव बढ़ सकता है। इससे मौद्रिक नीति पर भी असर पड़ सकता है क्योंकि वैश्विक मांग पूरी करने के लिए मुद्रा मुहैया कराने की मजबूरी देश की मौद्रिक नीतियों के साथ टकरा सकती है। रिपोर्ट में कहा गया है कि विदेशी मुद्रा में उतारचढ़ाव का जोखिम कम होने, अंतरराष्ट्रीय वित्तीय बाजारों तक बेहतर पहुंच के कारण पूंजी की लागत घटने, विदेशी मुद्रा भंडार की जरूरत कम होने जैसे फायदे मुद्रा के अंतर्राष्ट्रीयकरण के नुकसानों पर भारी पड़ते हैं।

अल्पकालिक उपाय के तौर पर समिति ने दो साल के भीतर भारतीय रुपये और स्थानीय मुद्राओं में बिल बनाने, निपटाने तथा भुगतान करने के लिए द्विपक्षीय एवं बहुपक्षीय व्यापार व्यवस्था संबंधी प्रस्ताव जांचने के लिए मानक प्रणाली तैयार करने का सुझाव दिया है।इसके अलावा भारत के भीतर तथा बाहर रहने नाले प्रवासियों के लिए (विदेशी बैंकों के नोस्ट्रो खातों के अलावा) रुपया खाते खोलने को बढ़ावा दिया जाना चाहिए। समिति ने सीमापार लेनदेन के लिये अन्य देशों के साथ भारतीय भुगतान प्रणालियों को एकीकृत करने और वैश्विक स्तर पर पांचों कारोबारी दिन 24 घंटे काम करने वाले भारतीय रुपया बाजार को बढ़ावा देकर वित्तीय बाजारों को मजबूत करने का सुझाव दिया है। समिति ने मध्यम अवधि की रणनीति के तहत दो से पांच साल में मसाला बॉन्ड (विदेशों में रुपये मूल्य में जारी होने वाले बॉन्ड) पर लगने वाला 5 प्रतिशत विदहोल्डिंग टैक्स हटाए जाने की सिफारिश की है। इससे पूंजी की लागत घटेगी। साथ ही सीमापार व्यापारिक लेनदेन के लिये आरटीजीएस के इस्तेमाल पर विचार किया जा सकता है। किसी मुद्रा को अंतरराष्ट्रीय मुद्रा तभी कहा जा सकता है जब उसका इस्तेमाल जारी करने वाले देश की सीमाओं के परे भी किया जा सकता हो और वह विनिमय के माध्यम के रूप में काम आ सके।

आश्चर्य नहीं होना चाहिए कि कई देश विदेशी मुद्रा वाला बनना चाहते हैं। कुछ देश इस दिशा में इसलिए भी प्रयास कर रहे हैं कि वे अमेरिकी डहलर से दूरी बनाना चाहते हैं। आंशिक तौर पर ऐसा भू-राजनीतिक वजहों से है।

आश्चर्य नहीं होना चाहिए कि कई देश विदेशी मुद्रा वाला बनना चाहते हैं। कुछ देश इस दिशा में इसलिए भी प्रयास कर रहे हैं कि वे अमेरिकी डॉलर से दूरी बनाना चाहते हैं। आंशिक तौर पर ऐसा भू–राजनीतिक वजहों से है। एक विचार यह भी है कि कि भारत को रुपये के अंतर्राष्ट्रीयकरण की दिशा में थोड़ा धीमी गति से बढ़ना चाहिए। रिपोर्ट की कुछ अनुशंसाओं से वृहद आर्थिक जोखिम भी बढ़ सकता है। उदाहरण के लिए रिपोर्ट की एक अनुशंसा यह है कि सभी सरकारी प्रतिभूतियों को पूर्ण पहुंच वाले माध्यम से जारी करना चाहिए और प्रयास किया जाना चाहिए कि सरकारी बॉन्ड को वैश्विक बॉन्ड सूचकांकों में शामिल किया जा सके।

वास्तव में रुपये का अंतर्राष्ट्रीयकरण एक हद तक भारत के पूंजीगत खाते के खुलेपन की क्षमता पर भी निर्भर करता है। यह बात भी ध्यान देने लायक है कि एक मुद्रा का अंतरराष्ट्रीयकरण जोखिम रहित नहीं होता है। वैश्विक बाजारों में अस्थिरता के दौर में रुपये या रुपये आधारित संपत्ति रखने वाले संस्थान उससे मुक्ति पाना चाहेंगे। इससे रुपये पर दबाव बढ़ सकता है।

भारत अब तक पूंजी खाते को लेकर सतर्कता से आगे बढ़ा है। अमेरिकी डॉलर अभी भी अंतर्राष्ट्रीय लेनदेन की प्रमुख मुद्रा है क्योंकि उसे एक बड़े, खुले और नकदीकृत बाजार का समर्थन हासिल है। नीति निर्माताओं के लिए यही बेहतर होगा कि वे रुपये के अंतर्राष्ट्रीयकरण की प्रक्रिया को सतत रखें और वित्तीय बाजारों के विकास तथा अंतर राष्ट्रीय अपेक्षाओं के अनुरूप मजबूत वृहद आर्थिक बुनियाद तैयार करने पर ध्यान दिया जाए। ❑❑

लेखक–पूर्व अपर आयकर आयुक्त दिल्ली।

जी–20 की बैठक में समावेशी शिक्षा पर बल

सा विद्या या विमुक्तये

पिछले एक दिसंबर 2022 से शुरू होकर अगले 1 दिसंबर 2023 तक चलने वाली जी–20 की बैठकों की अध्यक्षता भारत कर रहा है। जी–20 शिक्षा मंत्रियों की चौथी शिक्षा कार्य समूह बैठक गत 19 से 21 जून 2023 तक पुणे में संपन्न हुई। इस चौथी बैठक की अध्यक्षता केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने की, इसमें अतिथि देशों के साथ 14 मंत्रियों और 150 से अधिक प्रतिनिधियों ने हिस्सा लिया। इस बैठक में सभी ने यह बात स्वीकार की कि शिक्षा मानवता के भविष्य का वास्तुकार है, जिससे एक सभ्यता का निर्माण होता है। शिक्षा का उद्देश्य विकास, शांति, समृद्धि व मानव जाति का नेतृत्व करना है। जी–20 समूह के सारे प्रतिनिधियों ने मानवीय गरिमा और महिला सशक्तिकरण एक लचीले और न्याय संगत समावेशी समाज और टिकाऊ भविष्य के साथ मिलकर काम करने की आवश्यकता पर जोर दिया। लगभग आम राय थी कि उपरोक्त मूलभूत सिद्धांतों को अपनाकर के ही एक शिक्षित समाज का निर्माण किया जा सकता है। सभी सदस्य इस बात पर भी सहमत हुए कि उम्र, लिंग, सामाजिक, आर्थिक व सांस्कृतिक पृष्ठभूमि के बावजूद या जो लोग शारीरिक या मानसिक रूप से किसी कठिनाई का सामना कर रहे हैं, उन सब तक भी गुणवत्तापूर्ण समावेशी और न्याय संगत शिक्षा और प्रशिक्षण की पहुंच जल्दी से जल्दी उपलब्ध होनी चाहिए।

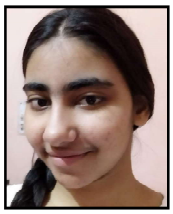

वर्तमान में शिक्षा पर खर्च किए जाने के मामले में भारत का स्थान दुनिया में 88 वें नंबर पर है। नई शिक्षा नीति में प्रावधान किया गया है कि पूरे देश में पांचवी कक्षा तक निश्चित रूप से तथा आठवीं तक वरीयता के आधार पर और उसके बाद एक स्वरूप में मातृभाषा और स्थानीय भाषा में छात्रों को शिक्षा दी जाएगी।

–वैदेही

शिक्षा का उद्देश्य केवल अकादमिक नहीं अपितु भविष्य के लिए तैयार करने और तकनीक व व्यवसाय व्यवसाई कौशल विकसित कर जीवन को सुगम बनाने की प्रक्रिया है। शिक्षा हमें आजीवन सीखने की प्रक्रिया में बनाए रखती है। इस सीखने की प्रक्रिया के तहत ही देश समाज में हो रहे तमाम डिजिटल परिवर्तनों के साथ समाज के उन हिस्सों को जो अब तक किन्ही कारणों से पीछे रह गए हैं को प्रशिक्षित कर आगे लाया जा सकता है।

सभी देशों के प्रतिनिधियों ने स्वीकार किया कि समाज में विकलांग लड़कियों के लिए, गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन कर रहे लोगों के बच्चों के लिए शिक्षा का बुनियादी ढांचा विकसित कर उनके भीतर व्याप्त शिक्षा के दंश को जल्दी से जल्दी दूर किया जाना चाहिए। इस हेतु सदस्य देशों ने सहभागिता निभाने की प्रतिबद्धता जाहिर की। गांव और शहरों के विद्यार्थियों के बीच मौजूद खाई को पाटने डिजिटल विभाजन को दूर करने और स्थानीय भाषाओं सहित प्रौद्योगिकी के साथ शिक्षण संस्थानों को प्रभावी रूप से क्रियाशील बनाने के लिए सामूहिक काम करने की साझा प्रतिबद्धता को भी दोहराया गया।

बैठक के दौरान और भी ढेर सारे मुद्दों पर चर्चा हुई। कागजों पर बड़े–बड़े आश्वासन भी दिए गए लेकिन आज तक जितनी शिक्षा नीतियां बनी उन सब में कुछ ना कुछ कमियां बाद में दिखी। उन कमियों को आगे कर उनमें व्यापक बदलाव की भी बात हुई। परंतु जमीनी सच्चाई आज

भी यही है कि शिक्षा क्षेत्र में कई एक विसंगतियां आज भी विद्यमान है।

नई शिक्षा नीति 2020 में शिक्षा को एक केंद्रीकृत रूप में पूरे भारत में लागू करने पर जोर दिया गया है। पर सवाल यह है कि व्यवहार में इतने विविधता पूर्ण देश में यह एकबारगी कैसे संभव होगा। भारत एक ऐसा देश है जहां 22 औपचारिक भाषाएं प्रचलित है। जितने राज्य अलग अलग संस्कृति के लोग हैं। रहन–सहन, खान–पान, वेशभूषा में भी वैविध्य है। लोकमन तो अलग है ही, संस्कृतियां भी अलग–अलग तरह की है। इतनी सारी विविधताओं से भरे समाज के लिए यह शिक्षा का केंद्रीकरण करना क्या उचित फलदाई हो सकता है। भारत का समाज और भारतीय समाज में जी रहे लोगों का मन मिजाज काफी लचीला रहा है। अनेक समाजशास्त्रीय अध्ययन उपलब्ध हैं जिसमें यह स्पष्ट किया गया है की सबको उनके अनुरूप ही जोड़कर रखा जा सकता है। इसीलिए भारत के लिए एक स्लोगन यह भी है यहां अनेकता में एकता है। उदाहरण के लिए सरकारी संस्थानों में मातृभाषा पर जोर देने की वजह से वे बच्चे गैर सरकारी संस्थानों में पढ़ने वाले बच्चों से अंग्रेजी में पिछड़ सकते हैं। नई शिक्षा नीति में भारतीय संस्कृति पर काफी महत्व दिया जा रहा है जिसके कारण आज प्राचीन और आधुनिक शिक्षा के मध्य संतुलन एक तरह से सिरे से गायब हो रहा है। भारतीय संस्कृति को समृद्ध करने के लिए प्राचीन गौरव को पुनर्जीवित करने, अलग तरह से परिभाषित करने की हड़बड़ी में इतिहास से उन पन्नों को धीरे–धीरे खत्म किया जा रहा है जिन्हें पढ़ने समझने की आज और आगे भी शिद्दत के साथ जरूरत महसूस की जाएगी।

शिक्षा सिर्फ एक शब्द नहीं है बल्कि क्रांति है जिससे समाज में बदलाव लाया जा सकता है। नेलसन मंडेला ने कहा था कि 'शिक्षा वह शक्तिशाली हथियार है जिससे आप दुनिया बदल सकते हो। हमारा भविष्य इस बात पर निर्भर है कि आज क्या तैयारी है शिक्षा ही आपको जानकार नागरिक बनाती है जो नागरिक आत्मनिर्भर होगा और सामाजिक अन्याय के खिलाफ लड़ने में सक्षम होगा। एक शिक्षित आदमी ही क्या सही है क्या गलत है, में फर्क कर सकता है।'

भारत में शिक्षा को संविधान के अंतर्गत मौलिक अधिकारों में शामिल किया गया है। अनुच्छेद 45, 6 वर्ष तक के बच्चों को शिक्षा देने की बात करता है। आजादी के बाद भारत की पहली शिक्षा नीति इंदिरा गांधी के समय 1968 में आई थी। कोठारी कमीशन के नाम से चर्चित यह समिति वर्ष 1964 से 1966 के दौरान अध्ययन के बाद कुछ सिफारिशें की थी। उन सिफारिशों में कहा गया था कि शिक्षा का उद्देश्य बच्चों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान करना, शिक्षा प्राप्ति के अवसर को बढ़ाना, त्रिभाषा फार्मूला को लागू करना तथा विदेशी विदेशी भाषाओं को सीखने पर भी जो दिया गया था। कोठारी समिति ने अपनी सिफारिश में विकलांग बच्चों अनुसूचित जाति जनजाति और लड़कियों की शिक्षा पर विशेष रूप से फोकस किया था।

इसके बाद वर्ष 1986 में राजीव गांधी ने शिक्षा नीति में बड़ा परिवर्तन किया और उनके जमाने में आई नई शिक्षा नीति ने प्रचलित शिक्षा नीति में आधुनिकता का पुट डालकर उसकी एक तरह से फिर से दोबारा ओवरहालिंग की थी। वर्ष 1986 में आई शिक्षा नीति में उन्होंने देश में ओपन यूनिवर्सिटी खोलने का रास्ता तैयार किया था।उसी रास्ते देश में पहली बार इंदिरा गांधी के नाम पर नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी की स्थापना की गई जिसे आज हम इग्नू के नाम से जानते हैं। ग्रामीण शिक्षा के विकास पर भी जोर देने की बात की गई साथ ही साथ कंप्यूटर और डिजिटल पुस्तकालय जैसे संसाधनों को जुटाकर शिक्षा के केंद्रीकरण की बात की गई। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 में देश में शिक्षा के विकास के लिए व्यापक ढांचा पेश किया गया। प्राथमिक शिक्षा पर बच्चों के स्कूल छोड़ने पर रोक लगाने के उद्देश्य से प्राथमिक शिक्षा को मुफ्त किया गया। गरीब परिवारों से आने वाले बच्चों के लिए पोषाहार की बात की गई। आर्थिक रूप से अत्यंत पिछड़े अनुसूचित जाति जनजाति अल्पसंख्यक समुदाय के बच्चों की शिक्षा के लिए आर्थिक सहयोग की भी बात की गई। महिलाओं के लिए व्यवसायिक और तकनीकी शिक्षा के लिए रास्ता तैयार किया गया। गरीब और उत्कृष्ट विद्यार्थियों के लिए नवोदय विद्यालय की परिकल्पना की गई जिसमें खासतौर पर गरीब बच्चों को विद्यालय में ही

रहकर पढ़ने की सुविधा प्रदान की गई। नई शिक्षा नीति ने देश के गैर सरकारी संगठनों को भी शिक्षा से जुड़कर सीधे लाभार्थियों तक पहुंचने तथा हाशिए पर बैठे लोगों को शिक्षा के केंद्र में लाने का ताना–बाना तैयार किया।

समय के साथ शिक्षा नीति में परिवर्तन किया जाता रहा है ताकि सीखने सिखाने की कोशिश कभी बाधित ना हो और साथ ही बच्चे और शिक्षक आसपास के वातावरण के अनुसार अपनी शैक्षिक पद्धतियों में आवश्यकता के अनुसार संशोधन भी कर सकें। 24 जून 2017 को इसरो के प्रमुख वैज्ञानिक के कस्तूरीरंगन की अध्यक्षता में 9 सदस्यों की एक समिति ने दोबारा नई शिक्षा नीति का मसौदा तैयार किया। इस शिक्षा नीति को केंद्रीय कैबिनेट ने 24 जुलाई 2020 को मंजूरी दे दी। इस शिक्षा में प्री प्राइमरी क्लासेज से लेकर बोर्ड परीक्षाओं अंडर ग्रेजुएट एडमिशन के तरीके आदि कई चीजों में कुछ अहम परिवर्तन किए गए हैं। स्कूली शिक्षा उच्च शिक्षा के साथ एग्रीकल्चर शिक्षा, चिकित्सक शिक्षा, तकनीकी शिक्षा आदि को भी जोड़कर एक एकीकृत स्वरूप प्रदान किया गया है, ताकि छात्रों को शिक्षा के साथ–साथ रोजगार के योग्य भी बनाया जा सके। शिक्षा नीति की सिफारिशों में आशा की गई है कि शिक्षा ऐसी होनी चाहिए जो अक्षर ज्ञान के साथ–साथ जीवनयापन का रास्ता भी आसान करें। इसीलिए शिक्षा के साथ–साथ कौशल विकास पर अत्यधिक जोर दिया गया है। नई शिक्षा नीति में दावा किया गया है कि शिक्षा पर जीडीपी का 6 प्रतिशत खर्च सुनिश्चित करने के लिए रास्ता तैयार किया जाएगा। ज्ञात हो कि वर्तमान में शिक्षा पर खर्च किए जाने के मामले में भारत का स्थान दुनिया में 88 वें नंबर पर है। नई शिक्षा नीति में प्रावधान किया गया है कि पूरे देश में पांचवी कक्षा तक निश्चित रूप से तथा आठवीं तक वरीयता के आधार पर और उसके बाद एक स्वरूप में मातृभाषा और स्थानीय भाषा में छात्रों को शिक्षा दी जाएगी। इस निर्णय से निश्चित रूप से छात्रों का संबंध अपनी मातृभाषा और स्थानीय भाषा से बना रहेगा। स्थानीय भाषा में पढ़ने से बच्चों की समझ विकसित होगी तथा अगर उच्च शिक्षा भी मातृ स्थानीय भाषा में उपलब्ध होगी तो उनका बेस मजबूत होगा। लेकिन दूसरे हाथ विदेशी विश्वविद्यालयों के लिए सारे दरवाजे खोल दिए गए हैं। ऐसे में भारतीय स्कूलों कालेजों से पढ़कर निकले छात्रों का मुकाबला सीधे विदेशी भाषाओं से शिक्षित प्रशिक्षित लोगों से होगा।

ऐसे में हमारी कोशिश समग्र शिक्षा के प्रति अधिक होनी चाहिए जहां सामाजिक ज्ञान, देशज ज्ञान, ऐतिहासिक ज्ञान और लोक भावना को आधुनिकता से जोड़कर पूर्ण नागरिक और आत्मनिर्भर भारत की आधारशिला रखी जा सके। लेकिन निश्चित रूप से उस तालीम के बारे में भी जगह बनानी ही होगी जिसके जरिए हम प्रतिस्पर्धियों का मुकाबला कर भारत को और अधिक मजबूत और समृद्ध देश बना सकें। ❑❑

:: सदस्यता संबंधी सूचना ::

अधिक जानकारी के लिए देखें :
http://swadeshionline.in/

मान्यवर,

स्वदेशी पत्रिका आज देश में चल रहे स्वदेशी आंदोलनों का स्थापित प्रतीक बन चुकी है। पिछले कई वर्षों से स्वदेशी पत्रिका ने असंगत एवं एकतरफा वैश्वीकरण, जनविरोधी आर्थिक उदारीकरण के विरोध एवं वैकल्पिक और रचनात्मक स्वदेशी आंदोलन के पक्ष में एक सक्रिय प्रहरी के नाते हमेशा आपको जागरूक बनाया है एवं आपसे संवाद स्थापित किया है। विगत कालखंड में इन सभी मुद्दों पर हमें आप जैसे सजग पाठकों का अपेक्षित सहयोग भी मिलता रहा है और भविष्य में भी मिलेगा ऐसा, विश्वास है।

आपसे आग्रह है कि स्वदेशी पत्रिका की आपकी सदस्यता अवधि यदि समाप्त हो गई हो तो कृपया पिछले समय से आगामी वर्ष तक की राशि धनादेश (मनीआर्डर), चेक एवं मांग पत्र (डिमांड ड्राफ्ट) के माध्यम से शीघ्र भेजने की कृपा करें। पत्रिका के लिफाफे के उपर चिपकाए गए पते की प्रथम पंक्ति में सदस्यता अवधि अंकित है। आप अपनी सदस्यता राशि ''स्वदेशी पत्रिका'' के नाम पत्रिका के कार्यालय के पते पर भेज सकते हैं। सदस्यता अद्यतन न हो पाने की स्थिति में वित्तीय कारणों से पत्रिका आगे जारी रखना कठिन होगा।

सदस्यता शुल्क निम्न प्रकार है :–

स्वदेशी पत्रिका	*वार्षिक*	*आजीवन*
हिन्दी	150 रुपए	1500/– रुपए
अंग्रेजी	150 रुपए	1500/– रुपए

हमें आपका सहयोग स्वदेशी आंदोलन को राष्ट्रव्यापी एवं जनोन्मुखी बनाने में प्रमुख भूमिका निभाएगा। कृपया स्वदेशी पत्रिका स्वयं भी पढ़ें एवं अन्य को भी पढ़ने के लिए प्रेरित करें। पत्रिका के संबंध में अपना निष्पक्ष विचार हमें अवश्य भेजें।

आप सीधे बैंक ऑफ इंडिया, खाता नं. **602510110002740, IFSC : BKID- 0006025 (Ramakrishnapuram)** में जमा करवा सकते हैं और उसकी रसीद और अपना पता आप कार्यालय में अवश्य भेजे।

स्वदेशी पत्रिका कार्यालय, 'धर्मक्षेत्र' शिव शक्ति मंदिर, सैक्टर–8, रामकृष्णपुरम्, नई दिल्ली–22

भारत में किसानों की आय हो रही है दोगुनी

भारत में लगभग 60 प्रतिशत आबादी आज भी ग्रामीण इलाकों में रहती है एवं इसमें से बहुत बड़ा भाग अपनी आजीविका के लिए कृषि क्षेत्र पर निर्भर है। यदि ग्रामीण इलाकों में निवास कर रहे नागरिकों की आय में वृद्धि होने लगे तो भारत के आर्थिक विकास की दर को चार चांद लगाते हुए इसे प्रतिवर्ष 10 प्रतिशत से भी अधिक किया जा सकता है। इसी दृष्टि से केंद्र सरकार लगातार यह प्रयास करती रही है कि किसानों की आय को किस प्रकार दुगुना किया जाय। इस संदर्भ में कई नीतियों एवं सुधार कार्यक्रम लागू करते हुए किसानों की आय को दुगुना किये जाने के प्रयास किए जा रहे हैं। अप्रेल 2016 में इस सम्बंध में एक मंत्रालय समिति का गठन भी केंद्र सरकार द्वारा किया गया था एवं किसानों की आय बढ़ाने के लिए सात स्त्रोतों की पहचान की गई थी। इनमें शामिल हैं, फसलों की उत्पादकता में वृद्धि करना, पशुधन की उत्पादकता में वृद्धि करना, संसाधन के उपयोग में दक्षता हासिल करते हुए कृषि गतिविधियों की उत्पादन लागत में कमी करना, फसल की सघनता में वृद्धि करना, किसान को उच्च मूल्य वाली खेती के लिए प्रोत्साहित करना (खेती का वीविधीकरण), किसानों को उनकी उपज का लाभकारी मूल्य दिलाना एवं अधिशेष श्रमबल को कृषि क्षेत्र से हटाकर गैर कृषि क्षेत्र के पेशों में लगाना। उक्त सभी क्षेत्रों में केंद्र सरकार द्वारा किए गए कई उपायों के अब सकारात्मक परिणाम दिखाई देने लगे हैं एवं कई प्रदेशों में किसानों के जीवन स्तर में सुधार दिखाई दे रहा है। किसानों की खर्च करने की क्षमता बढ़ी है एवं कुल मिलाकर अब देश के किसानों का आत्मविश्वास बढ़ा है।

केंद्र सरकार द्वारा किए गए उपायों के चलते फसलों और पशुधन की उत्पादकता में वृद्धि हुई है, संसाधनों के उपयोग में दक्षता आने से उत्पादन लागत में कमी आई है, फसल की सघनता में वृद्धि दर्ज हुई है। उच्च मूल्य वाली खेती की ओर विविधिकरण हुआ है।

– प्रहलाद सबनानी

प्राचीन भारत में तो सनातन संस्कृति का पालन करते हुए विशेष रूप से ग्रामीण इलाकों में गाय पालन की गतिविधियां बहुत बड़े स्तर पर चलाई जाती थी। उस खंडकाल में गाय पालन से दरअसल बहुत अधिक आर्थिक लाभ होता था। गाय के गोबर का इस्तेमाल खाद के रूप में किया जाता था, गाय के दूध से डेयरी उत्पादों का निर्माण कर बाजार में बेचा जाता था, गौ मूत्र का दवाई के रूप में इस्तेमाल किया जाता था, आदि। ग्रामीण इलाकों में किसी भी परिवार की सम्पन्नता इस बात से आंकी जाती थी कि किस परिवार में गाय की संख्या कितनी है। कृषि कार्य के अतिरिक्त लगभग समस्त परिवार गाय पालन की गतिविधि में भी संलग्न रहते थे एवं इससे यह उनकी आय का एक अतिरिक्त साधन बन जाता था। इसी तर्ज पर वर्तमान में केंद्र सरकार द्वारा ग्रामीण इलाकों में किसानों के लिए पशुपालन की गतिविधि को एक अतिरिक्त स्त्रोत के रूप में बढ़ावा दिया गया है।

पिछले 9 वर्षों के दौरान केंद्र सरकार द्वारा कृषि के लिए बजट आबंटन में अभूतपूर्व वृद्धि की गई है। वर्ष 2015–16 में कृषि बजट के लिए 25,460 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया था, जो वर्ष 2022–23 में बढ़कर 138,551 करोड़ रुपए का हो गया है। वर्ष 2019 में प्रधानमंत्री किसान योजना प्रारम्भ की गई थी। इस योजना के अंतर्गत प्रतिवर्ष रुपए 6000 की राशि, तीन समान किश्तों में, पात्र किसानों के बैंक खातों में सीधे ही केंद्र सरकार द्वारा जमा कर दी जाती

है। इस राशि का उपयोग पात्र किसान कृषि कार्य सम्पन्न करने के लिए खाद, बीज आदि खरीदते हैं। प्रधानमंत्री किसान योजना के अंतर्गत अभी तक 11.3 करोड़ पात्र किसान परिवारों को 2 लाख करोड़ रुपए से अधिक की धनराशि केंद्र सरकार द्वारा जारी की जा चुकी है।

देश में प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना को भी सफलतापूर्वक लागू किया गया है। प्राकृतिक आपदा की परिस्थितियों के बीच किसानों की फसल बर्बाद होने की स्थिति में बीमा कम्पनी द्वारा प्रभावित किसानों को हुए आर्थिक नुकसान की क्षतिपूर्ति की जाती है। इससे भारतीय किसानों का आत्म विश्वास बढ़ा है। कृषि क्षेत्र के लिए संस्थागत ऋण के लक्ष्य में अभूतपूर्व वृद्धि की गई है। पशु पालन और मत्स्य पालन के लिए प्रतिवर्ष 4 प्रतिशत ब्याज पर रियायती संस्थागत ऋण किसानों को उपलब्ध कराया जा रहा है। जिससे इन गतिविधियों में किसानों की लाभप्रदता बढ़ी है। किसान क्रेडिट कार्ड योजना के माध्यम से समस्त प्रधानमंत्री किसान योजना के लाभार्थियों को किसान क्रेडिट कार्ड योजना से जोड़ दिया गया है। विभिन्न उत्पादों का न्यूनतम समर्थन मूल्य उत्पादन लागत के डेढ़ गुने तक तय किया जा रहा है। भारत में जैविक खेती को बढ़ावा दिया जा रहा है जिसके कारण कीटनाशक दवाओं एवं उर्वरकों का कम इस्तेमाल होने लगा है एवं इससे किसानों के लिए कृषि पदार्थों की उत्पादन लागत कम हो रही है।

इसी प्रकार, राष्ट्रीय कृषि मंडी (ई–नाम) की स्थापना भी केंद्र सरकार द्वारा की गई है। इससे किसानों को अपने उत्पाद बेचने के लिए बेहतर बाजार मिला है। कृषि उपज लाजिस्टिकस में सुधार करते हुए किसान रेल की शुरुआत भी की गई है। इस विशेष सुविधा से विशेष रूप से फल एवं सब्जी जैसे पदार्थों के नष्ट होने की सम्भावनाएं कम हो गई हैं। देश में कृषि और सम्बंध क्षेत्र में स्टार्ट अप ईको सिस्टम का निर्माण भी किया जा रहा है। उत्पादकता एवं उत्पादन बढ़ाने के स्थान पर अब किसान की आय बढ़ाने हेतु नीतियों का निर्माण किया जा रहा है।

किसानों को 'प्रति बूंद अधिक फसल' के सिद्धांत का पालन करते हुए, सिंचाई सुविधाएं उपलब्ध कराई जा रहीं हैं। इस सम्बंध में सूक्ष्म सिंचाई कोष का गठन भी किया गया है। किसान उत्पादक संगठनों को प्रोत्साहन दिया जा रहा है ताकि किसान अपनी फसलों को उचित दामों पर बाजार में बेच सकें एवं इस संदर्भ में बाजार में प्रतियोगी बन सकें। कृषि क्षेत्र के यंत्रीकरण पर भी विशेष ध्यान दिया जा रहा है। खेत के मिट्टी की जांच कर किसानों को मृद्दा स्वास्थ्य कार्ड उपलब्ध कराए गए हैं, ताकि किसान इस मिट्टी में उसी फसल को उगाए जिसकी उत्पादकता अधिक आने की संभावना हो।

भारत में विभिन्न कृषि उत्पादों के उत्पादन में अतुलनीय वृद्धि के चलते अब भारत के किसान विभिन्न कृषि उत्पादों का निर्यात भी करने लगे हैं। भारतीय कृषि उत्पादों की अंतर्राष्ट्रीय बाजार में लगातार बढ़ रही मांग के चलते अब किसानों को इन उत्पादों के निर्यात से अच्छी आय होने लगी है। केंद्र सरकार ने कृषि उत्पादों के देश से निर्यात सम्बंधी नियमों को आसान किया है।

केंद्र सरकार द्वारा किए गए उक्त वर्णित कई उपायों के चलते फसलों और पशुधन की उत्पादकता में वृद्धि हुई है, संसाधनों के उपयोग में दक्षता आने से उत्पादन लागत में कमी आई है, फसल की सघनता में वृद्धि दर्ज हुई है। उच्च मूल्य वाली खेती की ओर विविधिकरण हुआ है। किसानों को उनकी उपज का लाभकारी मूल्य मिल रहा है एवं अतिरिक्त श्रमबल को कृषि क्षेत्र से हटाकर गैर कृषि क्षेत्र के पेशों में लगाया गया है। इन सबका मिलाजुला परिणाम यह हुआ है कि किसानों की शुद्ध आय में वृद्धि दृष्टिगोचर हो रही है। प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष दोनों रूप से किसानों की आय बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। ❑❑

प्रहलाद सबनानी, सेवा निवृत उप महाप्रबंधक,
भारतीय स्टेट बैंक, ग्वालियर, म.प्र.

:: सूचना ::

स्वदेशी पत्रिका आर्थिक सम्राज्यवाद के खिलाफ एक सशक्त आवाज है। पत्रिका को ऐसे लोगों से प्रतिक्रियाएं, रिपोर्ट या आलेख की अपेक्षा है जो राष्ट्रहित में सोचते हैं और देश के स्वावलम्बन के लिए कुछ करने की इच्छा रखते है। जरूरी नहीं कि आप पत्रकार या लेखक ही हों, अपने आसपास से जुड़ी चीजों के प्रति आपकी संवदेना है और आप शब्दों में उसे लिख सकते है तो हमें अवश्य लिख भेजें। साथ ही स्वदेशी पत्रिका में छपे लेख आपको कैसे लगते हैं, क्या आप इसमें कुछ नए विषयों का समायोजन चाहते हैं कृपया हमें अवश्य अवगत कराएं। आपके विचारों को हम प्राथमिकता के साथ प्रकाशित करने का भी प्रयास करेंगे।

संपादक, स्वदेशी पत्रिका

'धर्मक्षेत्र', सेक्टर–8, बाबू गेनू मार्ग, रामकृष्णपुरम्, नयी दिल्ली–110022

मेक इन इंडिया नहीं, बल्कि मेक बाई इंडिया बनना है: महाजन

स्वदेशी जागरण मंच के तत्वावधान में चामड़ गेट स्थित नई धर्मशाला में एक सेमिनार का आयोजन किया गया। मंच के राष्ट्रीय सह संयोजक, प्रमुख अर्थशास्त्री व स्वदेशी चिंतक डॉ. अश्वनी महाजन ने कहा कि जल्द ही भारत 10 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था बन जाएगा। दुनिया के अनेक छोटे–छोटे देश भारत के नेतृत्व में समृद्ध होंगे। उन्होंने कहा कि भारत को आत्मनिर्भर बनाने की बुनियाद 2014 में रखी जा चुकी है। अब हमें मेक इन इंडिया नहीं, बल्कि मेक बाई इंडिया बनना है। इससे देश के युवाओं को रोजगार मिलेगा। इस मौके पर जितेंद्र वर्मा को मंच का नगर संयोजक मनोनीत किया गया।

अध्यक्षता नन्नूमल गुप्ता ने की। सेमिनार में प्रांत सह संयोजक मनोज अग्रवाल, प्रांत समन्वयक ऋषि बंसल, स्वाबलंबी भारत अभियान की महिला समन्वयक डॉ. इंदु वार्ष्णेय, बुद्धसेन आर्य, नगर पालिका अध्यक्ष श्वेता चौधरी, गौरव आर्य, पूर्व सांसद लालबहादुर रावल, संतराज, दुर्गेश गुप्ता, पीपी सिंह, तरुण पंकज, हरीश वार्ष्णेय आदि मौजूद रहे।

https://www.amarujala.com/uttar-pradesh/hathras/india-has-to-become-make-by-india-ashwini-hathras-news-c-56-1-sali1016-1994-2023-07-10]

सोशल मीडिया से स्वदेशी पहुंचे घर–घर – श्रीवर्धन

स्वदेशी जागरण मंच ने युवाओं और गृहिणियों तक अपनी पहुंच बढ़ाने के लिये सोशल मीडिया के विभिन्न प्लेटफार्म पर अपने एकाउंट बनाये हैं। इनका लोकार्पण राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के राजस्थान क्षेत्र के प्रचारक प्रमुख श्रीवर्धन ने किया। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि संगठन को समयानुकूल चलने और इन माध्यमों का समाज और संगठन हित में प्रयोग करने की आवश्यकता है।

स्वदेशी जागरण मंच के विभाग संयोजक सोहन लाल शर्मा ने कहा कि हम काम को जिस गति से बढ़ाना चाहते हैं उसमें नई तकनीकों और माध्यमों का उपयोग समय की मांग है। अपने विचार और कार्यों को समाज के बीच ले जाने में इन सोशल साइट्स की महत्ती भूमिका है।

प्रांत के प्रचार प्रमुख धीरज बोधा ने कहा कि संगठन के स्वावलम्बी भारत अभियान में रोजगार और स्वावलम्बन पर विशेष काम किया जा रहा है। एकादशी के शुभ अवसर पर स्वदेशी जागरण मंच ने अपने फेसबुक प्रोफाइल, फेसबुक पेज, इंस्ट्राग्राम आईडी और ट्विटर एकाउंट को समाज में स्वदेशी के विचार और संगठन के कार्यों को जनता तक पहुंचाने के लिये लोकार्पित किया है। रोजगार की उपलब्धता, स्वावलम्बन के अवसर हों, कौशल विकास के कार्यक्रम हों या सरकारी योजनाएं, मंच इन माध्यमों से इनकी उपलब्धता सुगम करेगा। प्रांत के सभी 16 जिलों के प्रमुख कार्यकर्ता इसकी सदस्यता बढ़ाने और उपयोगिता के लिये काम करेंगे। लघु उद्योग, स्थानीय उद्योग और नए स्टार्टअप आदि को एक मंच उपलब्ध हो सकेगा। ऐसे युवा व्यवसायियों को भी प्रोत्साहित किया जाएगा जो नौकरी के पीछे न भागते हुए अपने पारिवारिक व्यवसाय को नई ऊंचाइयों पर ले गए हैं या स्वयं का व्यवसाय शुरू कर अन्य को भी रोजगार दे रहे हैं।

कार्यक्रम में स्वदेशी जागरण मंच के जिला संयोजक चंद्र शेखर चौबीसा, कोमल सिंह राठौड़, विभाग प्रचार प्रमुख सुरेश जोशी, सहकार भारती के प्रांत संगठक प्रदीप चौबीसा, विश्व संवाद केंद्र चित्तौड़ के प्रभारी कमल प्रकाश रोहिला आदि उपस्थित रहे।

https://livevns.news/state/rajasthan/svadeshi-jagaran-manch-udaipurphp/cid11457983.htm

हाथरस की हींग से महकेंगे देश–विदेश के बाजार

भारतीय व्यंजनों का स्वाद बढ़ाने वाली हींग को अब विश्व स्तर पर पहचान मिल चुकी है। उत्तर प्रदेश के एक जिला एक उत्पाद में शामिल हाथरस की हींग को जीआई टैग मिला है। इस उपलब्धि से हाथरस में 100 करोड़ से भी अधिक के हींग कारोबार को रफ्तार मिलेगी। जीआई टैग मिलने से देश–विदेश में हाथरस की हींग की मांग बढ़ेगी और निर्यात को गति मिलने से कारोबारियों के मुनाफा होगा। मालूम हो कि हाथरस की हींग का इतिहास 150

साल पुराना बताया जाता है। जिले में हींग की लगभग 100 फैक्ट्रियां हैं, जिनसे 1500 से अधिक लोगों का सीधे रोजगार जुड़ा हुआ है। यहां की हींग की क्वालिटी और शुद्धता के चर्चे पूरी दुनिया में है। देश में एक बड़ा तबका जो प्याज–लहसुन का सेवन नहीं करता। उनके लिए हींग खाने का स्वाद बढ़ाने वाला मैजिकल स्पाइस है।

ज्ञात हो कि हाथरस जिले के हींग के अलावा यहां के रंग, गुलाल, गारमेंट्स और नमकीन भी दुनियाभर में मशहूर हैं। आज भी हाथरस को हींग नगरी के अलावा रंग नगरी के नाम से जानते हैं। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि हाथरस में हींग की प्रोसेसिंग का कारोबार है, जहां हींग को खाने में इस्तेमाल के लिए तैयार किया जाता है। भारत में हींग की खेती नहीं होती। इसका कच्चा माल यानी रेजिन अफगानिस्तान, तजाकिस्तान, कजाकिस्तान आदि देशों से आयात होता है।

वर्ल्ड इंटलैक्चुअल प्रापर्टी आर्गेनाइजेशन की मानें को किसी भी उत्पाद को भौगोलिक संकेतिक यानी जीआई टैग दिलवाने की एक लंबी प्रोसेस होती है। इसके लिए राज्य सरकारों की ओर से उत्पाद की समस्त जानकारी और विशेषताओं के साथ आवेदन किया जाता है। यदि उत्पाद स्थान विशेष का उत्पाद के लिए विशेष महत्व होता है तो जीआई प्रमाणन जारी कर दिया जाता है। एक तरह से देखा जाए तो जीआई टैग अपने आप में किसी भी उत्पाद और स्थान विशेष के लिए बड़ी उपलब्धि है।

https://www.abplive.com/agriculture/up-one-district-one-product-harthras-hing-got-gi-tag-know-the-speciality-and-benefiys-of-hing-2378402

स्वदेशी से स्वावलंबन की ओर बढ़ रहा देशः पटेल

स्वदेशी वस्तुओं का उपयोग कर परिवार, समाज प्रदेश व राष्ट्र के विकास में सहयोग करने की भावना को लेकर स्वदेशी जागरण मंच पूरे प्रदेश और राष्ट्रीय स्तर पर जन जागरण का कार्यक्रम आयोजित कर रहा है। भारतीय मजदूर संघ के कार्यालय बिश्रामपुर में स्वदेशी जागरण मंच के प्रदेश संयोजक जगदीश पटेल ने सरगुजा संभाग की बैठक में अपना विचार व्यक्त करते हुए ये बातें कहीं।

बैठक का शुभारंभ भारत माता व स्वदेशी जागरण मंच के जनक राष्ट्रऋषि दंतोपत ठएगड़ी के चित्र के समक्ष दीप जलाकर किया गया। जगदीश पटेल ने कहा कि देश स्वदेशी से स्वावलंबन की ओर बढ़ रहा है। स्वावलंबन की ओर बढ़ते हुए विद्यालय, महाविद्यालय के छात्र–छात्राएं इंजीनियरिंग और कृषि के क्षेत्र में कार्य करने वाले कार्यप्रणालियों को विभिन्न पद्धतियों में परिवर्तन किया। पुराने समय में वार्षिक 2 लाख रुपए की कमाई करते थे। आज वह 10 से 15 लाख सलाना कमाई कर रहे हैं। उनकी आय का यह जरिया उन्हें आर्थिक रूप से स्वावलंबी बना रहा है। सरकार अधिक से अधिक संख्या में लघु व कुटीर उद्योग को भी बढ़ावा दे रही हैं, जिसमें 30 प्रतिशत अन्य पिछड़ा वर्ग व 60 प्रतिशत एससी, एसटी वर्ग को सब्सिडी मिल रही है। हमें उन लोगों तक पहुंचने की आवश्यकता है। उन्हें कहा कि काउंसलिंग करने की जरूरत है, जो आज इस लाभ से वंचित हो रहे हैं। स्वदेशी पहने, स्वदेशी दिखें स्वदेशी को एक आंदोलन का स्वरूप आज देने की जरूरत है। एक ईस्ट इंडिया कंपनी ने देश को गुलाम बना दिया था। आज हजारों

लाखों विदेशी कंपनी हमारे देश पर राज कर रही है और यहां से पैसा कमा कर अपने राष्ट्र को मजबूत कर रही है। हम सभी को अपने लोकल फॉर वोकल को मजबूत करते हुए राष्ट्र को मजबूत करने का प्रयास करना पड़ेगा।

छत्तीसगढ़ व मध्य प्रदेश के क्षेत्रीय संगठनमंत्री केशव दुबोलिया ने कहा कि छत्तीसगढ़ से अधिक संख्या में पलायन हो रहा है। यदि हम सब अपने ग्राम, नगर और प्रदेश वासियों को स्वदेशी के साथ जोड़ें, तो उनके आसपास उनके घर में ही बहुत सारे ऐसे कार्य हैं, जिससे उनका जीविकोपार्जन हो सकता है। इससे वे और भी आर्थिक रूप से संपन्न हो सकते हैं। इसके लिए मिलकर प्रयास करना होगा।

https://www.bhaskar.com/local/chhattisgarh/jashpur/news/the-country-is-moving-from-swadeshi-to-self-reliance-patel-131514447.html

चीन को पछाड़ भारत बना निवेशकों की पहली पसंद

विकासशील देशों में निवेश के लिए अब चीन नहीं बल्कि भारत निवेशकों की पहली पसंद बन गया है। इनवेस्को ग्लोबल की रिपोर्ट के मुताबिक, सोवरेन वेल्थ फंड के निवेश

को लेकर 142 मुख्य निवेश अधिकारियों ने भारत को पहली पसंद बताया। किसी देश के सरकारी फंड को सोवरेन फंड कहा जाता है। अपनी अर्थव्यवस्था व अपने नागरिकों की आर्थिक मजबूती के लिए दूसरे देशों में सोवरेन फंड का निवेश किया जाता है।

सर्वे के मुताबिक, वर्ष 2022 में सोवरेन फंड के निवेश के लिए चीन पहली पसंद था। पिछले साल चीन को निवेश की पसंद के मामले में 71 अंक मिले थे, जबकि भारत को 66 अंक। लेकिन वर्ष 2023 में किए गए सर्वे में भारत को 76 तो चीन को 51 अंक मिले। सर्वे में दक्षिण कोरिया, ब्राजील, मैक्सिको व दक्षिण अफ्रीका जैसे विकासशील देश भारत की तुलना में काफी पीछे पाए गए।

इनवेस्को के अध्ययन के मुताबिक, भारत की कारोबारी व राजनीति स्थिरता में लगातार बढ़ोतरी हो रही है जो उसका मजबूत पक्ष है। इसके अलावा भारत की आबादी, नियामक पहल और सोवरेन निवेशकों के लिए अनुकूल माहौल से भी भारत को निवेश की पहली पसंद बनने में मदद मिली।

निवेशकों का मानना है कि भारत की आबादी तेजी से बढ़ रही है और यहां कई दिलचस्प कंपनियां हैं। विदेशी कारपोरेट निवेश भी भारत में लगातार बढ़ रहा है। वहीं, भारत में महंगाई दर अन्य देशों के मुकाबले कम है और आर्थिक गतिविधियों के अधिकतर पैमाने भारत में सकारात्मक दिख रहे हैं। भारत का राजस्व संग्रह लगातार बढ़ रहा है और राजकोषीय घाटा कम हो रहा है।

https://www.jagran.com/business/biz-india-became-first-choice-for-investment-leaving-china-got-76-points-in-survey-23467324.html

रूस से तेल आयात पर भारत को 7.17 अरब डॉलर का फायदा

रूस–यूक्रेन में युद्ध छिड़ने के बाद रियायती रूसी कच्चे तेल की खरीद में इजाफा करके भारतीय रिफाइनरियों ने मई 2023 तक यानि 14 महीनों में कम से कम 7.17 अरब डॉलर की विदेशी मुद्रा बचाई है। भारत में रूसी कच्चे तेल पर छूट घटकर 4 डालर हो गई है। भारत के ट्रेड डेटा के विश्लेषण से इसका खुलासा हुआ है। बता दें कि भारत दुनिया में कच्चे तेल का तीसरा सबसे बड़ा उपभोक्ता है। यह अपनी 85 प्रतिशत से अधिक तेल जरूरतों को पूरा करने के लिए आयात पर निर्भर करता है। पिछले साल फरवरी में यूक्रेन पर रूस के आक्रमण से पहले, भारत फरवरी 2022 तक 12 महीनों में लगभग 44,500 बैरल प्रति दिन की खरीद के साथ रूसी कच्चे तेल का एक छोटा आयातक था।

रूस भारतीय रिफाइनरों को पश्चिम द्वारा लगाए गए 60 डॉलर प्रति बैरल मूल्य सीमा से कम कीमत पर तेल देता

है। पिछले साल फरवरी में यूक्रेन पर रूस के आक्रमण के बाद पश्चिमी देशों ने रूसी तेल आयात में कटौती कर दी और मास्को द्वारा दूसरी जगह तेल बेचने से होने वाली आय पर लिमिट लगा दी। अमेरिका और यूरोप के दबाव के बावजूद, भारत ने रूसी आयात पर पश्चिमी प्रतिबंधों का पालन करने से इनकार कर दिया है। भारत ने रूस से तेल खरीदने के अपने फैसले का बचाव करते हुए कहा है कि देश ऊर्जा आयात पर निर्भर है और लाखों लोग गरीबी में जी रहे हैं, इसलिए वह अधिक कीमत चुकाने की स्थिति में नहीं है। हालांकि, भारत में रूसी तेल का आयात 2022 की शुरुआत में बहुत कम आधार से बढ़ा, जो पूरे वर्ष में काफी बढ़ गया। भारत में 2022 में रूसी तेल का आयात दस गुना बढ़ गया।

भारतीय रिफाइनर, जो जमीन के नीचे से निकाले गए कच्चे तेल को पेट्रोल और डीजल जैसे तैयार उत्पादों में परिवर्तित करते हैं, अब रूसी तेल के सबसे बड़े खरीदार हैं। रियायती तेल के लिए भारतीय रिफ़ाइनर्स ने यूक्रेन–पूर्व युद्ध के समय में अपनी पूरी खरीद के 2 प्रतिशत से भी कम को बढ़ाकर 44 प्रतिशत कर लिया।

सरकारी कंपनियों इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन, हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड, भारत पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड, मैंगलोर रिफाइनरी एंड पेट्रोकेमिकल्स लिमिटेड और एचपीसीएल–मित्तल एनर्जी लिमिटेड के अलावा नीजि कंपनियां जैसे रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड और नायरा एनर्जी लिमिटेड रूस के साथ अलग से डील पर बातचीत जारी रखे हुए हैं। अगर एक साथ बात करतीं तो छूट और अधिक होती।

भारत में आने वाले रूसी तेल के प्रति दिन 2 मिलियन बैरल का लगभग 60 प्रतिशत हिस्सा सरकारी यूनिट्स के पास है। अगर ये कंपनियां एक साथ बात करतीं तो यह छूट अधिक हो सकती थी। समाचार एजेंसी पीटीआई के मुताबिक, भारतीय रिफाइनर डिलीवरी के आधार पर रूस से कच्चा तेल खरीदते हैं, जिससे शिपिंग और बीमा की व्यवस्था करने की जिम्मेदारी मास्को पर आ जाती है। ❑❑

https://www.livehindustan.com/business/story-indian-companies-saved-foreign-exchange-of-7-point-17-billion-dollar-by-buying-cheaper-crude-oil-from-russia-8419458.html

स्वदेशी गतिविधियां – स्वावलंबी भारत अभियान

अर्थ संचय अभियान

सचित्र झलक

जयपुर, राजस्थान

पश्चिमी विभाग, दिल्ली

चण्डीगढ़

मेरठ, उ.प्र.

रांची, झारखंड

फरीदाबाद, हरियाणा

जमशेदपुर, झारखंड

स्वदेशी पत्रिका डाक तिथि 15–16 जुलाई 2023
एल.पी.सी. दिल्ली, दिल्ली पी.एस.ओ., दिल्ली आर.एम.एस. दिल्ली–06
प्रकाशन तिथि : प्रत्येक माह 10 तारीख

डाक पंजी. संख्या DL-SW/01/4074/2021-23
रजि. आर.एन.आई. पंजी. संख्या 64697/96

स्वदेशी गतिविधियां – स्वावलंबी भारत अभियान

अर्थ संचय अभियान

सचित्र झलक

रोहिणी, दिल्ली

हाथरस, उ.प्र.

भीलवाड़ा, राजस्थान

जालंधर, पंजाब

प्रकाशक व मुद्रक डॉ. अश्वनी महाजन द्वारा स्वदेशी जागरण समिति के लिए काम्पीटेंट बाईन्डर्स (प्रिंटिंग यूनिट), नवीन शाहदरा, दिल्ली से मुद्रित और धर्मक्षेत्र, सेक्टर–8, रामाकृष्णपुरम्, नयी दिल्ली–110022 से प्रकाशित, संपादकः अजेय भारती